राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 345 , पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, शुक्रवार , 25 जून 2021 मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

पुरी और गोवा में नजर आया साल का आखिरी सुपरमून

पुरी, (एजेंसी)। ओडिशा के पुरी और गोवा के पणजी में गुरुवार की शाम खूबसूरत नजारा दिखा। दरअसल, यहां लोगों को आसमान में साल के आखिरी सुपरमून स्ट्राबेरीमून की झलक दिखाई दी। लोग इसे देखने के बाद काफी उत्साहित दिखे। इस दौरान चांद धरती के इर्द-गिर्द अपनी कक्षा में सबसे निकट होता है और इसलिए आम फुल मून से ज्यादा बड़ा और प्रकाशमय होता है। स्ट्रॉबेरी मून आमतौर पर स्प्रिंग के आखिरी फुल मून पर होता है।

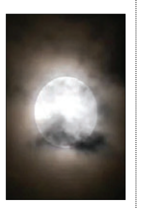

सबसे सस्ता स्मार्टफोन जियोफोन नेक्स्ट लॉन्च

मुंबई, (एजेंसी)। रिलायंस जियो और गूगल की साझेदारी में बना नया स्मार्टफोन जियोफोन नेक्स्ट गुरुवार को लॉन्च हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं सालाना आम सभा में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियोफोन नेक्स्ट की घोषणा की। नया स्मार्टफोन जियो और गूगल के फीचर्स और ऐप्स से लैस होगा। एंड्रॉयड बेस्ड इस स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जियो और गूगल ने मिलकर तैयार किया है। अंबानी ने ऐलान किया कि नया स्मार्टफोन आम आदमी की जेब के लिहाज से बनाया गया है, लिहाजा यह बेहद किफायती होगा। 10 सितंबर से इसकी बिक्री शुरू होगी। अंबानी ने कहा कि देश को 2जी मुक्त 5जी युक्त बनाना लक्ष्य है।

परमाणु सक्षम मिसाइल निर्भय का परीक्षण

बालासोर, (एजेंसी)। भारत ने 1000 किमी की दूरी की मारक क्षमता वाले अपनी सबसोनिक क्रूज परमाणु सक्षम मिसाइल 'निर्भय' का गुरुवार को ओडिशा में चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया। रक्षा शोध एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के सूत्रों ने बताया कि मिसाइल का परीक्षण सुबह 10.45 बजे किया गया। 'निर्भय' मिसाइल की तुलना अमेरिका के टॉमहॉक और पाकिस्तान के बाबर मिसाइल की तुलना से की जाती है। 300 किलोग्राम तक परमाणु अस्त्र ले जाने में सक्षम और अत्याधुनिक टैक्नालॉजी से लैस 'निर्भय' को जमीन की सतह, हवा अथवा पानी के नीचे पनडुब्बियों से भी छोड़ा जा सकता है।

निर्देशक सिवन का दिल का दौरा पड़ने से निधन

मुंबई, (एजेंसी)। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सिनेमेटोग्राफर और निर्देशक सिवन का दिल का दौरा पड़ने से गुरुवार को निधन हो गया है। 89 वर्षीय सिवन ने अपने घर में ही अंतिम सांस ली। सिवन के निधन पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी शोक व्यक्त किया है। बता दें कि फिल्मकार संगीत सिवन, संतोष सिवन और संजीव सिवन उनके बेटे हैं। पिता की मौत से आहत संगीत सिवन ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है। सिवन ने अपने ट्वीट में लिखा कि हर चीज के लिए शुक्रिया पापा, आपके बिना दुनिया को सोचना काफी मुश्किल है, लेकिन जो आपने रास्ता दिखाया है, हम उस पर चलते रहेंगे। हम

कुपवाड़ा में सड़क हादसे में दो मरे, आठ घायल

श्रीनगर, (एजेंसी)। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में गुरुवार को सड़क दुर्घटना में आठ माह के शिशु सहित दो लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि कुपवाड़ा में गुरुवार को बाघबेल्ला जब्दी पर एक वाहन पलट गया, जिसमें आठ माह के शिशु अफान और 90 वर्षीय वृद्ध सरदार अली शाह की मौके पर मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां सभी की हालत स्थिर है। उन्होंने बताया कि सभी कानूनी और चिकित्सीय कार्रवाई पूरी होने के बाद शवों को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की आठ दलों के 14 नेताओं के साथ चर्चा

परिसीमन के बाद जम्मू-कश्मीर में चुनाव

नई दिल्ली । जम्मू-कश्मीर में हाल में हुए जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), नेशनल कांफ्रेस समेत गुपकार गठबंधन के दलों ने भले ही अनुच्छेद-370 की वापसी की बात उठाई हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अब वे भी मान चुके हैं कि इसकी वापसी नहीं हो सकती। यही कारण है कि पीडीपी और नेशनल कांफ्रेस जैसे जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री के साथ गुरुवार को हुई बैठक में यह बात उठाई तो जरूर, लेकिन नेशनल कांफ्रेस ने साफ कर दिया कि वह कोई गैरकानूनी कदम नहीं उठाएगी, जो भी लड़ाई लड़नी होगी वह कानूनी रूप से लड़ेगी। हां, पीडीपी ने जरूर कहा कि वह संघर्ष करती रहेगी। जबकि कांग्रेस ने अनुच्छेद-370 की बात छेड़ने के बजाय सिर्फ डोमिसाइल की बात की। ऐसे में लगभग साढ़े तीन घंटे चली बैठक में मांग विधानसभा चुनाव और पूर्ण राज्य के दर्जे पर केंद्रित रही।

पीएम ने कहा, अब न दिल्ली की दूरी होगी और न दिल की दूरी- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से फिर भरोसा दिलाया गया कि परिसीमन होते ही चुनाव होंगे और सही वक्त आते ही पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल जाएगा। संवाद की इस शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री ने भरोसा

दिलाया, अब न दिल्ली की दूरी होगी और न दिल की दूरी। बैठक के बाद सभी ने विश्वास जताया कि यह कश्मीर के लिए अच्छा होगा। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 खत्म किए जाने के बाद से रुका हुआ संवाद गुरुवार को शुरू हुआ तो तेज गति से आगे बढ़ा।

दरअसल इस बैठक के लिए कोई एजेंडा तय नहीं किया गया था बल्कि सभी को यह अवसर दिया गया कि वे जो भी चाहें कहें। इसका असर भी दिखा। सभी ने माना कि बैठक बहुत अच्छे माहौल में हुई। मोटे तौर पर जो मुख्य मांगें आईं और खुद सरकार भी सकारात्मक दिखी उसमें परिसीमन और पूर्ण राज्य का दर्जा था। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की ओर से राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की भी बात कही गई। उनकी ओर से तीन दशकों के दौरान जम्मू-कश्मीर छोड़ चुके कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए हर प्रयास करने की भी मांग हुई।

आजाद ने नौकरियों और जमीन पर हक में डोमिसाइल (स्थानीय निवास) की शर्त रखने की भी मांग की। कुछ ऐसी ही मांगें दूसरे दलों ने भी की। बताते हैं कि पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ज्यादा मुखर थीं और उन्होंने कहा कि अनुच्छेद-370 को जिस तरह हटाया गया उसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। वह पाकिस्तान से बातचीत का मुद्दा भी उठा गईं। जबकि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब एक नया कानून बन गया है तो उनकी लड़ाई कानूनी होगी। यानी कहीं न कहीं यह भाव पैदा हो चुका है कि संविधान के नियमों के अनुरूप अनुच्छेद-370 को हटाया गया है, उसकी वापसी किसी जिद से नहीं हो सकती।

पूर्ण राज्य का दर्जा देने में चुनाव अहम- सभी के बोलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह पहले ही कह चुके हैं कि राज्य में चुनाव भी होगा और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा देने में चुनाव अहम कदम साबित होंगे। संकेत साफ था कि पूर्ण राज्य के दर्जे का फैसला चुनाव बाद होगा। दरअसल, आजाद ने चुनाव से पहले ही पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की थी।

10-12 वर्षों में शीर्ष तीन नौसैनिक शक्तियों में होगा भारत : राजनाथ सिंह

कारवार (कर्नाटक) । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत यहां विकसित किए जा रहे नौसैनिक अड्डे को एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा होना चाहिए। यदि जरूरत पड़ी तो इसके लिए वे बजट आवंटन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का लक्ष्य अगले 10-12 वर्षों में दुनिया की शीर्ष तीन नौसैनिक शक्तियों में स्थान बनाना है।

राजनाथ ने कहा, प्रोजेक्ट सीबर्ड को देखने और समझने से पहले मेरे मन में इसको लेकर एक उत्सुकता थी। कारवार को नजदीक से देखकर मुझे काफी खुशी हो रही है और इस नौसैनिक अड्डे को लेकर मेरे आत्मविश्वास का स्तर बहुत बढ़ गया है।

नौसैनिक अधिकारियों और नाविकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, इस परियोजना के पूरा होने से न सिर्फ भारत की रक्षा तैयारी मजबूत होगी, बल्कि इससे कारोबार, अर्थव्यवस्था और भारत की ओर से दी जाने वाली मानवीय मदद के काम में भी गति आएगी।

राजनाथ ने कहा, ऐसा कहा जा रहा है कि यह भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा होगा। लेकिन हमारी इच्छा है कि यह एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा हो। यदि इसके लिए जरूरत पड़ी तो हम बजट आवंटन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के साथ राजनाथ ने परियोजना क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस नौसैनिक अड्डे का भविष्य बहुत उज्ज्वल है और इसका सारा श्रेय अधिकारियों और नाविकों को जाता है।

देश की आलोचना करने लगे अब कांग्रेस नेता

भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने बोला प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में हमला

भोपाल, (रासं)। मप्र भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का शुभारंभ करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके नेता पीएम मोदी की आलोचना करते-करते देश की आलोचना करने लग गए हैं। कमलनाथ कहते हैं कि देश महान नहीं बदनाम है। दिग्विजय सिंह क्लब हाउस चैट में धारा 370 और 35 ए को लेकर सवाल उठाते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जिस काम को आप 70 सालों में नहीं कर सके, उसे मोदी जी ने कर दिखाया है।

वहीं कोरोना वेक्सीन पर कांग्रेस के सवालों पर नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने हमारे वैज्ञानिकों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया। मोदी सरकार पर सवाल उठाने वालों को यह जान लेना चाहिए कि स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की वैक्सीन हमारे देश में आने में 15 साल लग गए थे। पोलियो की वैक्सीन आने में सालों लगे थे। मोदी सरकार ने सिर्फनौ महीनों में देश में दो कंपनियां वैक्सीन बनाने लगी थीं। मप्रमें जिस तरह से एक ही दिन में 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगाकर रिकॉर्ड बनाया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री शिवराज जी और जनता को बधाई देता हूं।

दाढ़ी काटने का मामला

ट्विटर इंडिया के एमडी को हाईकोर्ट से राहत

गाजियाबाद, (एजेंसी)। बुलंदशहर निवासी बुजुर्ग की लोनी में दाढ़ी काटने के मामले में वायरल वीडियो को लेकर ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को पूछताछ के लिए गुरुवार को लोनी थाने पहुंचना था, लेकिन वह थाने नहीं पहुंच सके, क्योंकि उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए गाजियाबाद पुलिस को कहा है कि आप इस तरह सख्ती नहीं बरत सकते। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ कीजिए। मनीष माहेश्वरी ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट में कहा कि वह कंपनी के निदेशकों में शामिल नहीं हैं। कंपनी के निदेशक विदेश में बैठे हैं। वह यहां सेल्स एंड मार्केटिंग का काम देखते हैं, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी इसकी नहीं है कि ट्विटर पर कैसा कंटेंट डाला जा रहा है। उनका पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को उनसे सख्ती न बरतने के निर्देश दिए हैं साथ ही वर्चुअल माध्यम से पूछताछ के लिए कहा है।

गिरफ्तारी पर पांच दिन की रोक

सोमवार तक नहीं होगी गिरफ्तारी

कर्नाटक के कोर्ट ने आदेश दिया है कि सोमवार तक ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी की गिरफ्तारी नहीं होगी। इस बीच पुलिस को एमडी से कोई बयान दर्ज कराना है तो वह वर्चुअल बयान दर्ज करा सकते हैं।

31 जुलाई तक सभी बोर्ड जारी करें नतीजे

नई दिल्ली, (एजेंसी)। देश के सभी राज्य बोर्डों के लिए समान मूल्यांकन नीति बनाना असंभव है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कही है। दरअसल, कोर्ट 24 जून को कक्षा बारहवीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि प्रत्येक बोर्ड स्वायत्त और अलग है। इसलिए अदालत इन्हें समान योजना अपनाने निर्देश नहीं दे सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, प्रत्येक बोर्ड अपनी योजना करे तैयार

न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा कि हम पूरे देश के विद्यार्थियों के लिए समान योजना बनाने का निर्देश नहीं दे सकते हैं। प्रत्येक बोर्ड को अपनी योजना तैयार करनी होगी। उन्हें इसके बारे में ज्यादा पता है और उनके पास सही सलाह देने वाले विशेषज्ञ भी मौजूद हैं।

आंध्र प्रदेश बोर्ड ने रद्द कीं परीक्षाएं

नई दिल्ली, (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश सरकार ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है, शिक्षा मंत्री ए सुरेश ने गुरुवार को यह जानकारी दी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को चेतावनी दिए जाने के कुछ ही घंटों बाद आया है।

सुनवाई खत्म होने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बोर्डों को 10 दिन में मूल्यांकन की योजना अधिसूचित करने व 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन के नतीजे घोषित करने के निर्देश दिए हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कारवार नेवल बेस पहुंचे और वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, सीएनसी वेस्टर्न नेवल कमांड ने रियर एडमिरल महेश सिंह, एफओके के साथ उनका स्वागत किया।

तमिलनाडु में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के मुकदमे होंगे वापस

चेन्नई, (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र के कृषि कानूनों और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हुए प्रदर्शन के खिलाफ दर्ज किए गए सभी मामलों को गुरुवार को वापस लेने की घोषणा की। श्री स्टालिन ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का उत्तर देते हुए कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में कोविड बाद क्लिनिक खोले जाएंगे।

उन्होंने कहा कि दो औद्योगिक इकाईयां स्थापित की जाएंगी, जिससे 22,000 लोगों को रोजगार मिलेगा तथा मीडिया के खिलाफ सभी मानहानि के मामले भी वापस लिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना बाद जटिलताओं को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ कोविड बाद क्लीनिक खोले जाएंगे। द्रमुक प्रमुख ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए उत्तरी तमिलनाडु में दो नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवकों और महिलाओं को रोजगार का अवसर मुहैया कराने तथा उत्तरी तमिलनाडु में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए चेय्यार और तिंदीवनम में दो नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिसमें क्रमशः 12,000 और 10,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के लिए चीन की हरकतें जिम्मेदार : भारत

नई दिल्ली । भारत ने गुरुवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में पिछले साल सीमा पर चीन द्वारा बड़ी संख्या में सैनिकों को जमा करने और इसकी स्थिति को एकतरफा तौर पर बदलने की कोशिश करने से क्षेत्र की शांति भंग हुई। भारत की यह टिप्पणी चीन द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद सामने आई है, जिसमें उसने कहा था कि उसने क्षेत्र में आत्मरक्षा के तहत सैनिकों को तैनात किया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीन द्वारा बड़ी संख्या में सैनिकों को एकत्र करने और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर यथास्थिति को बदलने की एकतरफा कोशिश से शांति भंग हुई। बागची ने यह प्रतिक्रिया तब दी जब उनसे गतिरोध को लेकर सवाल पूछा गया था। बागची ने कहा, चीन की हरकतें 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन हैं। इनके तहत दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति बनी थी कि दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करेंगे और इन क्षेत्रों में सैनिकों की उपस्थिति को न्यूनतम रखेंगे।

सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा के लिए गुरुवार को कजाखस्तान के अपने समकक्ष मेजर जनरल तलगत ममितायेविच कोइबाकोव के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। कजाखास्तान की चीन के साथ 1780 किलोमीटर सीमा मिलती है। लेकिन भारत के विपरीत कजाखस्तान का चीन के साथ कोई सक्रिय सीमा विवाद नहीं है।

दूसरी लहर के दौरान पासपोर्ट सेवा का बना रहा उच्च मानक: एस जयशंकर

नई दिल्ली । कोरोना वायरस महामारी के बावजूद नागरिकों को समय पर पासपोर्ट जारी करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को अधिकारियों की सराहना की। जयशंकर ने पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोरोना की दूसरी लहर के दौरान विदेश मंत्रालय और अन्य एजेंसियों द्वारा पासपोर्ट सेवा का उच्च मानक बनाए रखने का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा, महामारी के बावजूद हमने समय पर पासपोर्ट की आपूर्ति को जारी रखा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द-से-जल्द महामारी से पूर्व के समय के स्तर तक पहुंच जाएंगे।जयशंकर ने कहा कि मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम से 174 भारतीय दूतावासों एवं वाणिज्य दूतावासों को जोड़ रखा है। उन्होंने कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा वैश्विक पहुंच कार्यक्रम जारी है।

नंदीग्राम में हार : ममता की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में निर्णय सुरक्षित

कोलकाता ■ एजेंसी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दोबारा मतगणना कराने की मांग वाली याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

न्यायमूर्ति कौशिक चंद की अदालत में सुनवाई के लिए सीएम ममता बनर्जी वर्चुअली हाजिर हुईं। जस्टिस ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्होंने कहा कि कानून के तहत इस पर फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि, जज की ओर से फैसला सुनाने की तारीख का जिक्र नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में चुनाव बाद हुई मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए फिर से मतगणना कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मार्च-अप्रैल में बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। 2 मई को चुनाव नतीजे घोषित किए गए। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थीं। उनके खिलाफ भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें 1957 वोटों से हरा दिया। इसके बाद ममता बनर्जी ने दावा किया कि मतगणना के दौरान धांधली की गई और मतगणना में लगे अधिकारियों को सुवेंदु अधिकारी और उनके अन्य सहयोगियों ने जान से मारने तक की धमकी दी।

जज बोले- न्यायिक तरीके से होगा फैसला

पुड्डुचेरी मंत्रिमंडल में 40 साल के बाद महिला मंत्री

पुड्डुचेरी, (एजेंसी)। केंद्रशासित प्रदेश पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने अपने मंत्रिमंडल में महिला मंत्री शामिल करने का निर्णय लिया है और यह राज्य के इतिहास में 40 साल से अधिक के अंतराल के बाद होगा। इससे पहले 1980 में कांग्रेस-द्रमुक गठबंधन सरकार में पहली बार रेणुका अप्पादुरई को मंत्री के रूप में शामिल किया गया था और उन्हें शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया था। पुड्डुचेरी मंत्रिमंडल का का गठन 27 जून को होगा।

1980 में रेणुका बनी थीं मंत्री

एनआर कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक कराईकल क्षेत्र में नेदुनगडु की विधायक चंदिरा प्रियांगा को रंगासामी नीत सरकार में शामिल किया जा रहा है।

आयोजन | एनएसए की बैठक : अजीत डोभाल ने स्पष्ट किया भारत का इरादा

लश्कर-जैश पर हो कड़ी कार्रवाई

दुशांबे, (एजेंसी)। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल गुरुवार को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य राष्ट्रों के उच्च सुरक्षा अधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के एनएसए की बैठक के दौरान अजीत डोभाल आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को साफ कर दिया। डोभाल ने स्पष्ट किया कि एससीओ को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों पर एक्शन लेना ही होगा।

एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर और जैश के खिलाफ एक्शन लेने की कार्य योजना बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एससीओ को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई करनी ही होगी। आतंकी वित्तपोषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उस पर हमला बोला और कहा कि आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने पर जोर दिया।

आतंकवाद पर नकेल कसने को दी कार्य योजना: एससीओ की बैठक के दौरान अजीत डोभाल ने शंघाई सहयोग संगठन के ढांचे के हिस्से के रूप में आतंकी संगठन लश्कर और जैश के खिलाफ कार्य योजना का प्रस्ताव रखा।

भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के विरोध में जुटे किसान, हिसार में तनाव

हिसार (हरियाणा), (एजेंसी)। हिसार में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है। बुधवार को किसानों ने काले झंडे दिखाकर शांतिपूर्वक विरोध करने का ऐलान किया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है और अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया गया। गुरुवार को सुबह से ही भाजपा कार्यालय से थोड़ी दूरी पर बैरियर लगा दिए गए। सेक्टर 14 के पास पुलिस ने नाका लगाकर वाहनों की एंट्री बंद कर दी है। नाराज किसानों ने भाजपा कार्यालय के पास लगे झंडे और फ्लेक्स फाड़ दिए।

झंडे और फ्लेक्स फाड़े

भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में रविवार को हिसार, फतेहाबाद, भिवानी और सिरसा के पदाधिकारी हिसार में जुटेंगे। पदाधिकारी चंडीगढ़ और दिल्ली के नेताओं से वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़, सीएम मनोहरलाल चंडीगढ़ से अपना संबोधन देंगे।

सार समाचार

कोविड-19 जांच रिपोर्ट को लेकर बोला झूठ, इस इस्लामिक धर्मगुरू को दी गई 4 साल की सजा

जकार्ता। कोरोना वायरस से संक्रमित होने की बात छुपाने के मामले में इंडोनेशिया के प्रभावशाली धर्मगुरू मुहम्मद रिजिक शिहाब को बृहस्पतिवार को चार साल कैद की सजा सुनाई गई। 'ईस्ट जकार्ता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट' के तीन न्यायाधीशों के एक पैनल ने कहा शिहाब ने अपनी कोविड-19 जांच रिपोर्ट के संबंध में झूठ बोला था, जिससे उनके सम्पर्क में आए लोगों की पहचान करने में परेशानी आई। वह 13 दिसम्बर से ही हिरासत में हैं। न्यायाधीशों ने कहा कि जितना समय वह जेल में बिता चुके है, वह उनकी सजा से कम कर दिया जाएगा। फैसला सुनाने से पहले अदालत के बाहर भारी पुलिस बल और सेना के जवान तैनात किए गए थे। शिहाब की रिहाई की मांग करते हुए उनके हजारों समर्थकों ने वहां रैली निकालने की कोशिश की, जिस कारण अधिकारियों को अदालत आने वाले मार्ग को बंद करना पड़ा। पुलिस ने उनके समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें भी कीं।

फिलीपीन के पूर्व राष्ट्रपति बेनिग्नो एक्विनो का 61 वर्ष की आयु में निधन

मनीला। फिलीपीन के पूर्व राष्ट्रपति एवं देश के सबसे प्रमुख लोकतंत्र समर्थक राजनीतिक परिवार के वंशज बेनिग्नो एक्विनो तृतीय का मंगलवार को निधन हो गया है। वह 61 वर्ष के थे। एक्विनो के एक रिश्ते के भाई और जनसम्पर्क अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पूर्व सीनेटर बैम एक्विनो ने कहा कि वह अपने भाई के निधन से काफी दुःखी हैं। उन्होंने कहा, '' उन्होंने अपना पूरा जीवन फिलीपीन वासियों को समर्पित कर दिया।'' परिवार के सदस्यों ने उनके निधन से जुड़ी विस्तृत जनकारी मुहैया नहीं कराई। बेनिग्नो को मंगलवार सुबह महानगर मनीला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके पूर्व कैबिनेट अधिकारी, रोजेलियो सिंगसन ने बताया कि बेनिग्नो एक्विनो का 'डायलिसिस' किया जाता था और जल्द ही उनका 'किडनी ट्रांसप्लांट' किया जाना था। एक्विनो 2010 से 2016 तक देश के राष्ट्रपति थे। वह एक राजनीतिक परिवार के उत्तराधिकारी थे, जिसे फिलीपीन में सत्तावाद के खिलाफ एक बांध के रूप में देखा जाता था। उनके पिता एवं पूर्व सीनेटर बेनिग्नो एस एक्विनो जूनियर की 1983 में मनीला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सैन्य हिरासत में हत्या कर दी गई थी। उनकी मां कोराज़ोन एक्विनो ने 1986 के ''जनशक्ति'' विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसके कारण तानाशाह फर्डिनेंड मार्कोस को अपदस्थ होना पड़ा था।

न्यूजीलैंड पुलिस ने गिरोहों, अपराधियों से 35.3 करोड़ डॉलर जब्त किए

वैलिंगटन, 24 जून (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड सरकार के पुलिस मंत्री पोटो विलियम्स ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने पिछले चार वर्षों में गिरोहों और अपराधियों से लगभग 50 करोड़ डॉलर (35.3 करोड़ डॉलर) जब्त कर चुकी है। विलियम्स ने कहा कि इन गिरोहों को हमारी कम्युनिटी का शोषण करके पैसा नहीं कमाना चाहिए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि सरकार संगठित अपराध और गिरोहों को बर्दाश्त नहीं करेगी और उन्हें रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। मंत्री ने कहा, हमारी सफलता उन गिरोहों को मारने की हमारी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाती है, जब उन्हें नुकसान होता है । पुलिस मंत्री ने कहा कि सरकार अपराधिक कानूनी कार्यवाही में भी संशोधन करेगी।

टीकाकरण से इनकार करने वाले 153 अमेरिकी अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई

ह्यूस्टन। अमेरिकी शहर ह्यूस्टन के एक अस्पताल के कम से कम 153 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत या तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, या नौकरी से निकाल दिया गया है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी बुधवार को एक रिपोर्ट में टेक्सास ट्रिब्यून ने कहा कि ह्यूस्टन मेथोडिस्ट ने 153 कर्मचारियों को निकाल दिया या उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। रिपोर्टर में कहा गया है कि अप्रैल में ह्यूस्टन मेथोडिस्ट ने अपने कर्मचारियों को अपनी नौकरी बचाए रखने के लिए 7 जून तक वैक्सीन प्राप्त करने की आवश्यकता की घोषणा की थी। अस्पताल के 24,947 कर्मचारियों ने टीकाकरण कराया है। अस्पताल ने 178 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया, जो समय सीमा तक ऐसा करने में विफल रहे थे, उन्हें टीकाकरण साबित करने के लिए दो और सप्ताह का समय दिया गया था। अस्पताल के प्रवक्ता के अनुसार, उन कर्मचारियों में से पच्चीस लोगों को टीका लगाया गया था। इस महीने की शुरूआत में एक संघीय जिला अदालत के न्यायाधीश ने उन कर्मचारियों में से एक के द्वारा लाए गए मुकदमे को खारिज कर दिया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि नीति गैरकानूनी थी।

ईरान ने वेबसाइट डोमेन पर कब्जा जमाने के अमेरिका के कदम की निंदा की

तेहरान। ईरानी सरकार ने दर्जनों वेबसाइट डोमेन को जब्त करने के अमेरिका के कदम की अभिव्यक्ति की वैश्विक आजादी को कमजोर करने और मीडिया में स्वतंत्र आवाजों को चुप कराने के एक व्यवस्थित प्रयास के रूप में निंदा की है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को एक बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादेह ने वॉशिंगटन द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में दोहरे मानक को अपनाए जाने की बात को शर्मनाक कहते हुए उसकी आलोचना की। खतीबजादेह ने बयान में कहा, अमेरिका के मौजूदा प्रशासन ने ठीक पिछले प्रशासन के रास्ते का अनुसरण किया है, जिसका परिणाम और कुछ नहीं, बल्कि वॉशिंगटन को एक बार और हार का सामना करना होगा।

भारत सहित 183 देशों ने किया अमेरिका के इन प्रतिबंधों का विरोध

संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)।

भारत सहित 183 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें क्यूबा पर लगी अमेरिकी आर्थिक पाबंदियों को समाप्त करने की मांग की गई है। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि लगातार प्रतिबंध लगे रहने से बहुपक्षवाद तथा स्वयं संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता कमजोर होती है। अमेरिका और इज़राइल ही केवल इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं, जिसे 1992 से हर साल अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा भारी समर्थन के साथ अनुमोदित किया जाता है। महासभा ने 1992 से ही हर साल इस मुद्दे पर मतदान शुरू किया था। यह प्रस्ताव लगातार 29वें साल, बुधवार को पारित हुआ, जिसमें क्यूबा के खिलाफ अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंध को समाप्त करने की मांग की गई है। पिछले साल कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।

मध्य अफ्रीकी गणराज्य, म्यांमां, मोलदोवा और सोमालिया ने वोट नहीं किया। वहीं, कोलंबिया, यूक्रेन और ब्राजील ने उस प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जो '' एक बार फिर इस तरह के कानूनों तथा उपायों को लागू करने वाले देशों से, उनके कानूनी शासन के अनुसार जल्द से जल्द इन्हें निरस्त या अमान्य करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता है।'' संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान विश्व निकाय में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर मयंक सिंह ने कहा, '' अंतरराष्ट्रीय समुदाय को, प्रतिबंधों से मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयास तेज करने की जरूरत है। भारत को उम्मीद है कि प्रतिबंध जल्द से जल्द वापस ले लिए जाएंगे।

भारत क्यूबा द्वारा पेश किए प्रस्ताव के मसौदे का समर्थन करता है।'' उन्होंने कहा, ''इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि इस सभा द्वारा व्यक्त की गई विश्व की राय के विपरीत, इस प्रतिबंध का निरंतर अस्तित्व, बहुपक्षवाद तथा संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। '' सिंह ने कहा कि बहुपक्षवाद में अटूट विश्वास के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत पूरी एकजुटता के साथ इसमें महासभा के साथ खड़ा है। इस तरह के प्रतिबंधों से प्रभावित देश की आबादी, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर असर पड़ता है। वे अन्य चीजों के अलावा विकास, भोजन, चिकित्सा देखभाल और सामाजिक सेवाओं के अधिकार सहित मानवाधिकारों का फायदा भी नहीं उठा पाते।

फेसबुक के ईमोजी के खिलाफ जारी हुआ फतवा, मौलाना ने कहा- अल्लाह के प्यार के लिए इस तरह की चीजें बंद करें

ढ़ाका। (एजेंसी)।

बांग्लादेश में एक मशहूर मौलाना हैं नाम है अहमदुल्ला, जिनका फेसबुक पर ऑफिशियल अकाउंट भी है और लाखों फॉलोअर्स भी हैं। अक्सर ही टीवी पर दिखाई देते हैं और ज्यादातर मुस्लिम बहुल्य बांग्लादेश में धार्मिक मामलों पर ही चर्चा करते हैं। लेकिन वो इन दिनों अपने अजीबो-गरीब फतवा को लेकर चर्चा में हैं। धर्म के नाम पर मौलाना द्वारा फतवा जारी किए जाने कि खबर तो आम है। लेकिन सोशल मीडिया पर फेमस इस मौलाना ने इमोजी के खिलाफ ही फतवा जारी कर दिया। दरअसल, मौलाना ने फेसबुक के 'हाहा' ईमोजी के खिलाफ फतवा जारी किया है। सोशल मीडिया पर फेमस मौलाना अहमदुल्ला ने फेसबुक पर लोगों का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली इमोजी 'हाहा' के खिलाफ फतवा जारी करते हुए ऐसा करने को गलत बताया है। मौलाना ने तीन मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इसमें फेसबुक पर हाहा इमोजी के जरिए लोगों का मजाक उड़ाए जाने को लेकर बात की है। मौलाना के इस वीडियो को 20 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। उन्होंने कहा कि आप इस इमोजी का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए कर रहे हैं और पोस्ट करने वाले व्यक्ति का इरादा बुरा नहीं है तो ये ठीक है। लेकिन अगर आपका इरादा सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले व्यक्ति को बदनाम करना या फिर उसे ताना मारना है तो ये इस्लाम में पूरी तरीके से हराम है। मौलाना अहमदुल्ला ने वीडियो को सोशल मीडिया पर डालकर कहा कि अल्लाह के प्यार के लिए मैं आपसे कहता हूं कि इस तरह की चीजें करना बंद करें।

इजराइल की नयी सरकार का बड़ा कदम, वेस्ट बैंक में बस्तियों के निर्माण की 31 परियोजनाओं को दी मंजूरी

यरूशलम। इजराइल के एक रक्षा मंत्रालयी निकाय ने बुधवार को वेस्ट बैंक में बस्तियों केनिर्माण की 31 परियोजनाओं को बुधवार को आगे बढ़ाया। देश की नयी सरकार के तहत कार्यभार संभालने के बाद यह पहला ऐसा कदम है। इजराइली मीडिया ने खबर दी कि सिविल प्रशासन द्वारा स्वीकृत योजना में एक खरीदारी केंद्र, विशेष जरूरतों वाला एक स्कूल और अवसंरचना की कई परियोजनाएं एवं मौजूदा वेस्ट बैंक बस्तियों में कुछ परिवर्तन शामिल हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की नयी सरकार ने इस महीने की शुरुआत में शपथ लेकर लंबे समय तक इस पद पर रहे बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल कर दिया था। कई अंतरराष्ट्रीय समुदाय इजराइली बस्ती निर्माण को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध और फलस्तीनियों के साथ शांति स्थापित करने में बाधा मानते हैं। 1967 के मध्यपूर्व युद्ध में क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद,इजराइल ने वेस्ट बैंक में दर्जनों बस्तियों का निर्माण किया है जहां 4,00,000 से ज्यादा इजराइली करीब 30 लाख फलस्तीनियों के साथ-साथ रह रहे हैं। फलस्तीनी वेस्ट बैंक को भविष्य के स्वतंत्र राष्ट्र के मुख्य हिस्से के तौर पर देखते हैं। दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ताएं कई वर्षों से स्थगित हैं। अमेरिका ने इजराइल और फलस्तीन दोनों से ऐसे कार्यों से बचने की अपील की है जो शांति प्रयासों में बाधा डालते हों। इनमें बस्तियों का निर्माण भी शामिल है।

जापान का पुराना मिहामा परमाणु संयंत्र ऑनलाइन हुआ

टोक्यो (एजेंसी)।

जापान के समुद्र तट पर फुकुई प्रान्त में पुराना मिहिमा परमाणु संयंत्र ऑनलाइन वापस आ गया है। ये सरकार की अनिवार्य 40 वर्ष की सीमा से परे परिचालन के लिए पहला रिएक्टर है, जिसे 2011 फुकुशिमा परमाणु संकट के बाद चालू किया गया था। ये जानकारी स्थानीय मीडिया ने गुरुवार को दी है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मिहामा संयंत्र में विवादास्पद नंबर 3 परमाणु रिएक्टर के संचालक कंसाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने कहा कि यूनिट को लगभग 10 वर्षों तक ऑफलाइन रहने के बाद बुधवार को फिर से चालू कर दिया गया।

संयंत्र के संचालक ने कहा कि इस दौरान रिएक्टर, जिसे 44 साल पहले पहली बार परिचालन में लाया गया था, उसमें सुरक्षा कार्य और निरीक्षण किया गया है। संयंत्र के संचालकों के अनुसार, फुकुशिमा आपदा के बाद 40 वर्ष की आयु की जापान की इकाइयों के बीच सबसे पहले पुराने रिएक्टर को वापस ऑनलाइन लाया गया, इसके इंजीनियरों ने यूनिट के अंदर से नियंत्रण छड़ें निकालना शुरू कर दिया है। परमाणु रिएक्टरों के संचालन पर सरकार द्वारा अनिवार्य 40 साल की सीमा 2011 के संकट के बाद रखी गई थी, लेकिन अगर एक रिएक्टर जापान के परमाणु विनियमन प्राधिकरण (एनआरए) द्वारा सुरक्षा जांच पास करता है, तो रिएक्टर का परिचालन जीवन साठ साल तक बढ़ाया जा सकता है। 2016 में एनआरए द्वारा मिहामा नंबर 3 यूनिट के लिए इस तरह की मंजूरी दी गई थी, जो कि स्थानीय समुदाय, जापान के निकटतम पड़ोसियों और व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए बहुत अधिक है। फुकुई और क्योटो और शिगा के पड़ोसी प्रान्तों में, इस सप्ताह की शुरूआत में ओसाका जिला न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें मिहामा नंबर 3 रिएक्टर के निलंबन पर जोर दिया गया था। वादी के अनुसार, यदि आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा भूकंप आता है तो मिहामा संयंत्र में नंबर 3 इकाई जैसे पुराने रिएक्टरों के खराब होने की संभावना अधिक होती है। उन्होंने तर्क दिया कि 40 साल की परिचालन सीमा का मूल रूप से सरकार द्वारा अनिवार्य, बिना किसी अपवाद के पालन किया जाना चाहिए। ये दुनिया का सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखियों जैसी विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त देश है।

भारत के बयान पर बोला चीन- सीमा मुद्दे को द्विपक्षीय संबंधों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए

बीजिंग। (एजेंसी)।

चीन ने कहा कि भारत के साथ लंबित सीमा मुद्दे को शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए और इसे द्विपक्षीय संबंधों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। भारत के साथ लगी सीमा पर चीन की सैन्य तैनाती को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर के मंगलवार को कतर आर्थिक मंच पर दिये गये बयान के बारे में पूछे जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि सीमा मुद्दे को द्विपक्षीय संबंधों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जयशंकर ने कहा था कि भारत के साथ विवादित सीमा पर चीन की सैन्य तैनाती और बीजिंग सैनिकों को कम करने के अपने वादे को पूरा करेगा या नहीं, इस बारे में अनिश्चितता दोनों पड़ोसियों के संबंधों के लिए चुनौती बनी हुई हैं। लिजियान ने यहां मीडिया ब्रीफिंग में कहा, ''हमें सीमा मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए और हमें नहीं लगता कि सीमा मुद्दे को हमारे द्विपक्षीय संबंधों से जोड़ा जाना चाहिए। सीमा के पश्चिमी सेक्टर में चीन की सैन्य तैनाती सामान्य रक्षात्मक व्यवस्था है। यह संबंधित देश द्वारा चीन के क्षेत्र के खिलाफ अतिक्रमण या खतरे को रोकने के लिए है।'' चीन के विदेश मंत्रालय ने बाद में मंत्रालय की वेबसाइट पर अपने जवाब में लिखा, ''चीन हमेशा से बातचीत के माध्यम से सीमा के मुद्दे के शांतिपूर्ण हल के लिए तैयार है और सीमा के विषय को द्विपक्षीय संबंधों से जोड़ने के विरुद्ध है।'' जयशंकर ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद से संबंधित व्यापक विषय यह है कि क्या भारत और चीन आपसी संवेदनशीलता और सम्मान पर आधारित संबंध बना सकते हैं और क्या बीजिंग सीमावर्ती क्षेत्र में दोनों पक्षों द्वारा किसी बड़े सशस्त्र बल को तैनात नहीं करने की लिखित प्रतिबद्धता का पालन करेगा। पूर्वी लद्दाख में 5 मई, 2020 को चीन और भारत के बीच सैन्य गतिरोध शुरू हुआ था और 45 साल में पहली बार दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए थे।

पैंगोंग झील क्षेत्र से सैनिकों की पूरी तरह वापसी की दिशा में सीमित प्रगति हुई है। दोनों पक्ष अब टकराव के बाकी बिंदुओं पर सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया के लिए वार्ता में लगे हैं। भारत विशेष रूप से हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग से सैनिकों की वापसी पर जोर दे रहा है। पिछले महीने भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में टकराव के सभी बिंदुओं से सैनिकों की पूरी तरह वापसी के बिना तनाव कम नहीं हो सकता है तथा भारतीय सेना क्षेत्र में हर तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।

भारत की वह स्पेशल फोर्स जो रखती है लद्दाख में चीन की हर हरकत पर नजर

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

चीन की मिलिट्री ने भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की तर्ज पर एक खास तरह की पोस्ट तैयार की है. इस खास फोर्स को चीन ने लद्दाख के करीब चुंबी घाटी में तैनात है. भारत और चीन के बीच एलओसी पर हुए टकराव के बाद से चीन ने तिब्बती युवाओं की भर्ती शुरू कर दी है. खबर के मुताबिक अब तक तिब्बती युवाओं वाले दो बैच की भर्ती हो चुकी है और हर मैच में 100 युवा है. इन्हें पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी के साथ ही ट्रेनिंग दी गई है.

बता दें कि भारत ने तिब्बती नागरिकों के लिए स्पेशल फोर्स काफी समय पहले ही तैयार की थी. जिसे 7 विकास बटालियन के रूप में जाना जाता है. इसबटालियन का कोड 22 है और कभी-कभी इसे इस्?टैब्लिशमेंट टू-टू भी कहते हैं. इस स्?पेशल फोर्स में तिब्बत के निर्वासित नागरिकों को तरजीह दी जाती है. नवंबर 1962 में चीन के साथ पहले युद्ध के खत्म होने के बाद यह फोर्स अस्तित्व में आई. इस फोर्स का मुखिया उस समय बीएन बीएन मलिक को नियुक्त किया गया था. बता दें कि इस फोर्स तिब्बती नागरिकों को शामिल किया गया, जो सन् 1959 के बाद भारत में बतौर शरणार्थी आए थे और तिब्बत वापस जाकर चीन के चंगुल से उसे आजाद कराना चाहते थे. इस फोर्स ने 1971 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ हुए युद्ध के दौरान योगदान भी दिया था.

26/11 हमले की साजिश में शामिल तहव्वुर राणा के व्यक्तिगत प्रत्यर्पण मामले की तारीख तय

वाशिंगटन (एजेंसी)।

लॉस एंजिलिस में एक संघीय अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा के व्यक्तिगत प्रत्यर्पण के मामले में तारीख तय कर ली है। भारत में 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले में संलिप्तता के कारण वह वांछित है। भारत सरकार के अनुरोध पर प्रत्यर्पण की सुनवाई लॉस एंजिलिस में मजिस्ट्रेट्र जज जैकलीन चुलजियान करेंगी। अदालत के रिकॉर्ड बताते हैं कि अमेरिकी सरकार ने इस सप्ताह दो बार अदालत के समक्ष सीलबंद भारतीय दस्तावेज सौंपे हैं। एक दस्तावेज बुधवार को सौंपा गया। अनुरोध पर दस्तावेजों की सामग्री को सीलबंद किया गया है। प्रत्यर्पण पर सुनवाई स्थानीय समयानुसार दिन में डेढ़ बजे और अंतरराष्ट्रीय समयानुसार शुक्रवार, 25 जून को रात दो बजे होगी। यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया के अदालतकक्ष के उपलिपिक ने बृहस्पतिवार के लिए निर्धारित सुनवाई सूची के बारे में बताया जिसमें अमेरिका सरकार बनाम तहव्वुर राणा (व्यक्तिगत हिरासत) भी शामिल है। अमेरिका ने अदालत के समक्ष कई अभिवेदनों में ''प्रत्यर्पण के प्रमाणन संबंधी अनुरोध के पक्ष में अमेरिका के जवाब'' के समर्थन में घोषणा की है।

राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में शामिल होने के मामले में भारत में वांछित है। राणा लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली का बचपन का दोस्त है। भारत के अनुरोध पर राणा को मुंबई आतंकवादी हमले में संलिप्तता के आरोप में लॉस एंजिलिस में 10 जून, 2020 को फिर से गिरफ्तार किया गया था। मुंबई हमले में छह अमेरिकी नागरिकों समेत 166 लोग मारे गये थे। भारत ने उसे भगोड़ा घोषित किया है। पाकिस्तानी मूल का 60 वर्षीय अमेरिकी नागरिक हेडली 2008 के मुंबई हमलों की साजिश रचने में शामिल था। वह मामले में गवाह बन गया था और हमले में अपनी भूमिका के लिए वर्तमान में अमेरिका में 35 साल जेल की सजा काट रहा है। अमेरिका का कहना है कि 59 वर्षीय राणा का भारत में प्रत्यर्पण भारत और अमेरिका के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के अनुरूप है।भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक, भारत सरकार ने राणा के औपचारिक प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है और अमेरिका ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमेरिका सरकार ने दलील दी है कि भारत प्रत्यर्पण के लिए राणा सभी मापदंडों को पूरा करता है। अमेरिका ने कहा कि वह राणा को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए प्रमाणन का अनुरोध करता है और प्रत्यर्पण अनुरोध में संभावित कारण स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं तथा राणा ने भारत के अनुरोध को खारिज करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है।

सभी निर्वाचन क्षेत्रों में रैपिड रिस्पांस टीम बनाएगा दिल्ली जलबोर्ड

कच्चे पानी की समान तरीके से आपूर्ति करने का खोजना होगा तरीका: चड्ढा

नई दिल्ली (एजेंसी)।

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने राजधानी में बेहतर जलापूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में रैपिड रिस्पांस टीम बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत जिन क्षेत्रों से गंदे पानी की आपूर्ति या कम पानी आपूर्ति की सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त होती हैं, वहां पर शिकायतों को जल्द दूर किया जाएगा। दरअसल, गुरुवार को डीजेबी के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने मुख्य अभियंताओं, वरिष्ठ अधिकारियों और सदस्यों (जल) के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में दिल्ली के भीतर उपलब्ध पानी के पाइप और टैंकर द्वारा समान वितरण, निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर पानी की कमी और दूषित पानी समेत विधायक और वार्ड स्तर के साथ-साथ सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायतों को कम करने के लिए एक रैपिड रिस्पांस टीम का गठन करने पर चर्चा की गई। इस दौरान राघव चड्ढा ने कहा कि जनसंख्या और प्रति व्यक्ति उपयोग आदि महत्वपूर्ण मानकों के मॉडल के आधार पर राजधानी में पानी की आपूर्ति का रोड मैप बनाना चाहिए। इसी से अधिकतम उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाई जा सकती है। हमें उपलब्ध कच्चे पानी की आपूर्ति के लिए पाइप नेटवर्क या अतिरिक्त टैंकर के माध्यम से समान आपूर्ति का तरीका खोजने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि शिकायतों का बिना किसी देरी के तुरंत निवारण किया जाए। डीजेबी उपाध्यक्ष ने जल आपूर्ति से जुड़े सदस्यों, सीई, एसई और ईई के प्रभारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। सभी 70 निर्वाचन क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रबंधन की समीक्षा की और सदस्यों को सख्त निर्देश दिए कि संगठन में किसी भी अधिकारी के किसी भी प्रकार के ढुलमुल रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गंदे पानी की शिकायत, पानी की लाइन में लीकेज, कम दबाव वाला पानी, पानी की आपूर्ति नहीं होने, पानी की बर्बादी आदि जैसे मापदंडों पर एक के बाद एक सभी निर्वाचन क्षेत्रों की गहन समीक्षा की गई। राघव चड्ढा ने कहा कि सभी मुख्य अभियंताओं को क्षेत्र के विधायकों के साथ-साथ अपने संबंधित क्षेत्रों का दौरा करने की आवश्यकता है। पानी से जुड़े सभी मुद्दों को हल करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करें और उपाध्यक्ष कार्यालय में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में साप्ताहिक रिपोर्ट जमा कराएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से नियमित डीजेबी को मिले पानी का विश्लेषण किया जाए की कितना पानी मिला, मांग और आपूर्ति के बीच में कितना अंतर है। जिन क्षेत्रों से गंदे पानी की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति नहीं होने, पानी की कम आपूर्ति आदि के संबंध में सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन शिकायतों को जल्द दूर किया जाए। इसके अलावा राघव चड्ढा ने मुख्य अभियंताओं और अधीक्षक अभियंताओं के रैपिड रिस्पांस टीम की तैनाती पर भी विशेष जोर दिया। अपने क्षेत्र के विधायकों से मिलने और साइट दौरे के बाद विशेष कार्य योजनाओं का प्लान तैयार करेंगे। इन योजनाओं को सत्यापन और आगे की कार्रवाई के लिए जल सदस्यों को दिया जाएगा।

इस योजना के लागू होने से उम्मीद है कि डीजेबी को मिलने वाली शिकायतों की संख्या में कमी आएगी। उपाध्यक्ष ने दिल्ली जल बोर्ड को सभी आवश्यक प्रयास करने और गंभीर स्थिति से निपटने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से योजना तैयार करने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया। जिससे शिकायतों की संख्या और निस्तारण के बीच के अंतर को कम किया जा सके। राघव चड्ढा ने कहा कि यह सही समय था जब हमने लक्षित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके गंदे पानी की आपूर्ति आदि जैसे मुद्दों के दीर्घकालिक, व्यवहारिक समाधान पर चर्चा की। हमें उपलब्ध कच्चे पानी की आपूर्ति के लिए रास्ता खोजना होगा। जिससे अंतिम बिंदु तक पानी को बिना किसी नुकसान के पहुंचना होगा और अधिकतम उपभोक्ता को राहत पहुंचाने का लक्ष्य रखना होगा।

माध्यमिक और तृतीयक टैपिंग में प्रवाहमापी लगाने की आवश्यकता पर दिया बल

राघव चड्ढा ने फ्लोमीटर लगाने के स्टॉक का भी जायजा लिया और प्रत्येक मुख्य अभियंता को अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। उन्होंने पानी की आपूर्ति की मात्रा पर निगरानी के लिए माध्यमिक और तृतीयक टैपिंग में प्रवाहमापी लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। जबकि प्राथमिक बिंदुओं पर फ्लो मीटर पूरी तरह से लगाए गए हैं। किसी विशेष बिंदु से पानी के प्रवाह को मापने के लिए फ्लो मीटर आवश्यक हैं। ये जल ऑडिटिंग और रिसाव के नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। वे पीने योग्य पानी की आपूर्ति के नुकसान को कम करने के साथ-साथ उचित प्रबंधन में भी मदद करते हैं। इसके अलावा किसी भी संभावित रिसाव का पता लगाने में मदद करते हैं। डीजेबी उपाध्यक्ष ने जल सदस्यों को निर्देश दिया कि निर्वाचन क्षेत्रवार प्राप्त जल आपूर्ति के साथ निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार पानी की आपूर्ति, गंदे पानी की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति न होने और पानी की कमी आदि की शिकायतों को देखने के लिए एक टेबल बनाएं। इसके जरिए विशिष्ट समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करें।

एक नजर

इग्नू ने शुरू किया मास्टर ऑफ आर्ट्स ज्योतिष

नई दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज ने ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से ज्योतिष (एमएजेवाई) में मास्टर प्रोग्राम शुरू किया है। मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री (ज्योतिष) कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को ज्योतिष ज्ञान के विभिन्न भागों का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना है जिसमें भारतीय ऋषियों द्वारा युगों-युगों से विकसित ज्योतिष पर आधारित ग्रहों की गति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और अंतरिक्ष में होने वाली घटनाएं आदि शामिल हैं। इस कार्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों को यह भी ज्ञान प्राप्त होगा कि ज्योतिष का अध्ययन कैसे किया जाता है ।इस कार्यक्रम की अध्ययन सामग्री के माध्यम से छात्रों को प्राचीन भारत में ज्योतिषीय गणित, सिद्धांत और परिणामों की अवधारणा का विशेष ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ ज्योतिष का पूरा ज्ञान प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम छात्रों को ज्योतिष के क्षेत्र में रोजगार योग्य होने की क्षमता विकसित करने में मदद करेगा। इस डिग्री कोर्स के लिए छात्र की पात्रता में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उच्च डिग्री होनी चाहिए। पाठ्यक्रम की अवधि-2 वर्ष है, जिसका माध्यम हिंदी है। छात्र विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं।

पूर्व महापौर जेपी ने गुलाबी बाग क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट उद्घाटन किया

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के पूर्व महापौर जय प्रकाश ने गुरूवार को संजय नगर, गुलाबी बाग क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद अरविंद गर्ग व अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। जय प्रकाश ने बताया कि ये ऑक्सीजन प्लांट पूर्व पार्षद अरविंद गर्ग और सामाजिक कार्यकर्ता अमन आहूजा ने लगवाया है। उन्होंने कहा की कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान जैसे नागरिकों को दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के कारण परेशान होना पड़ा था वैसे तीसरी लहर में ना होना पड़े इस के लिए ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। उन्होंने बताया आगे भी रिहायशी क्षेत्रों में ऐसे ऑक्सीजन प्लांट लगाएं जाएंगे ताकि दिल्ली में नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन की कमी के कारण परेशान ना होना पड़े और उन्हें घर के निकट ही ऑक्सीजन मिल सके।

कोरोना नियम का पालन नहीं करने पर शराब की दुकान को कारण बताओ नोटिस

नई दिल्ली। राज्य आबकारी विभाग ने राजधानी दिल्ली में कोविड-19 महामारी के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का पालन नहीं करने को लेकर शराब की एक दुकान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

एनडीएमसी ने वर्ष 2021-2022 के लिए स्वास्थ्य लाइसेंस शुल्क में बढ़ोत्तरी की

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी)क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियों जैसे होटल, रेस्तरां, कॉफी शॉप, लॉजिंग हाउस, मिठाई की दुकानें और दैनिक खाने-पीने योग्य सामान बेचने वाले छोटे स्टॉल कियोस्क को चलाने के लिए विभिन्न ट्रेड लाइसेंसों के जारी करने या नवीनीकरण के लिए स्वास्थ्य लाइसेंस शुल्क में वार्षिक वृद्धि को 23 अगस्त 2018 के परिषद के निर्णय के अनुसार 1अप्रैल 2021 से लागू करने की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत छोटे कियोस्क स्टॉल मदर डेयरी बूथ, वाटर ट्रॉली आदि के लिए कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। शेष श्रेणियों में भी न्यूनतम बढोतरी 100 रुपए से लेकर 1700 रुपए वार्षिक किया जाएगा, लेकिन इसमें 5 सितारा होटल शामिल नही होंगे । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद इस साल स्वास्थ्य लाइसेंस के लिए करीब 200 मामलों पर कार्रवाई करेगी। इन मामलों में से 25 प्रतिशत मामलों के लिए स्वास्थ्य लाइसेंस शुल्क में कोई वृद्धि नहीं होगी, जिसमें सभी छोटी दुकानें, स्टॉल, पानी की ट्रॉली आदि शामिल हैं। इस निर्णय के अनुसार 40 प्रतिशत मामलों में 400 रुपए की वृद्धि होगी 30 प्रतिशत मामलों में 900 रुपए की वृद्धि होगी, 2 प्रतिशत मामलों में 100 रुपए और पांच सितारा होटलों आदि को कवर करने वाले 1 प्रतिशत मामलों में 4300 रुपए की वृद्धि प्रति मामला प्रति वर्ष के लिए की गई है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम जल्द विकसित करेगी पांच मिनी फारेस्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम जल शक्ति अभियान कैच द रेन कार्यक्रम के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र में अगले 14 से15 दिनों में 5 मिनी फारेस्ट विकसित करेगी। उन्होंने बताया कि ये मिनी फारेस्ट 1 सी-ब्लॉक स्थित पार्क, आजादपुर मंडी, 2 बी. 4, ब्लॉक पार्क, प्राथमिक विद्यालय के पास, सुलतानपुरी 3, जी. ब्लॉक पार्क, प्रशांत विहार 4, पॉकेट-2, पार्क सेक्टर-25, रोहिणी 5, पॉकेट-8 पार्क, सेक्टर-24, रोहिणी। उन्होंने बताया कि निगम ने कुल 8 मिनी फारेस्ट में से 3 मिनी फारेस्ट दो करोलबाग क्षेत्र व एक केशवपुरम क्षेत्र में विकसित किया जा चुका है और बाकी पांच अगले 14 से15 दिनों में विकसित किए जाएंगे। इसके लिए पौधे रोटरी कलब द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्षा जल संग्रहण के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 474 स्थानों बनाए है, जो भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि 13 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है और इस उद्देश्य के लिए 127 और स्थलों का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम अपने क्षेत्रों को हरा-भरा बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि नागरिकों को स्वच्छ हवा और शुद्ध वातावरण मिल सके। गोयल ने बताया कि उत्तरी नगर निगम ने पिछले साल 27330 पेड़ और 37756 झाड़ियां लगाई थी और इस साल भी 20,000 पेड़ और 30ए000 झाड़ियां लगाने का प्रस्ताव है।

भाजपा ने वैक्सीनेशन के प्रचार के लिए दिखाई झंडी

नई दिल्ली (एजेंसी)।

> प्रदेश भाजपा सैकड़ों हेल्प डेस्क खोलकर वैक्सीन लगाने के प्रति लोगों को जागरुक कर रही: आदेश गुप्ता

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने गुरूवार को वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत की जिसके तहत उन्होंने प्रदेश कार्यालय से टीकाकरण प्रचार के लिए 70 वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन दिल्ली के सभी 70 विधानसभाओं में जाएंगे और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरुक करने के साथ यह भी जानकारी देंगे कि वैक्सीनेशन कितना फायदेमंद हैं। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री एवं वैक्सीनेशन के संयोजक कुलजीत सिंह चहल, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवराहा एवं राजन तिवारी,प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख नवीन कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि वैक्सीन कोरोना के लिए सुरक्षा कवच है। इसलिए कोरोना मुक्त भारत का सपना साकार करने के लिए सभी को वैक्सीन लगना जरुरी है। केंद्र सरकार द्वारा सिर्फ दिल्ली को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है, इसलिए बिना किसी देरी के सबको वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। आदेश गुप्ता ने कहा कि वैक्सीन के प्रति लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है, भारत धीरे-धीरे कोरोना मुक्त होने की ओर है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गए ऐलान के तहत मुफ्त वैक्सीनेशन का अभियान पूरे देश में एक उत्सव के रुप में मनाया जा रहा है। रिकॉर्ड 86 लाख लोगों का एक ही दिन में वैक्सीनेशन करवाना इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार कितनी संवेदनशील है और वह हर नागरिकों की चिंता करती है।

केजरीवाल भूल गए हैं जनता के साथ किया अपना वादा: नेता प्रतिपक्ष

नई दिल्ली (एजेंसी)।

दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बदलते चरित्र पर हैरानी व्यक्त की है। उन्होंने पूछा है कि आखिर क्या कारण हैं कि केजरीवाल जनता के साथ किए अपने सारे वादे भूल गए हैं। वीआईपी संस्कृति के खिलाफ नारे लगाते हुए उन्होंने जनता से वादा किया था कि आम आदमी पार्टी जीती तो हम न बड़े बंगले लेंगे और एक कमरे के फ्लेट बनेंगे, न सुरक्षा लेंगे और न ही सरकारी गाड़ियां लेंगे। केजरीवाल समेत सारे मंत्री तो बंगलों में रह ही रहे हैं, अब केजरीवाल अपने बंगले की मरम्मत के नाम पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। भाजपा विधायकों ने कहा है कि 2013 में जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने मीडिया के सामने यह कहा था कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा लेकिन 47 दिनों में ही सरकार गिरने के बाद जब 2015 में दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उनके रंग-ढंग बदल गए। उनके पास अभी 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर जो बंगला है। जिस बंगले में वह रह रहे हैं, उनमें 5 बेड रूम, एक डायनिंग एरिया, गेस्ट रूम, दो ऑफिस 300 व्यक्तियों की क्षमता वाले दो लॉन, मीटिंग के लिए एक बड़ा और एक छोटा हॉल, दो सर्वेन्ट क्वार्टर और न जाने क्या-क्या है। क्या केजरीवाल इस बंगले से भी संतुष्ट नहीं है कि अब इसकी मरम्मत के नाम पर ही 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अपने आपको गरीब जनता का हमदर्द कहने वाला दिल्ली की जनता के खून-पसीने की कमाई को किस तरह उड़ा रहा है, यह अब सारी जनता देख रही है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने यह भी पूछा है कि क्या केजरीवाल के बंगले की मरम्मत के काम के लिए दिल्ली अर्बन आर्ट कमिशन की मंजूरी ले ली गई है। अर्बन आर्ट कमिशन ने 19 नवंबर को इस मरम्मत के काम को एक बड़ा झूठ बताया था। कमिशन ने इस बंगले की मरम्मत के बारे में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग उसे धोखे में रखने की कोशिश कर रहा है। पीडब्ल्यूडी ने अर्बन आर्ट कमिशन को लिखा था कि बंगले में सिर्फ कुछ तब्दीली और कुछ हिस्सा जोड़ा जा रहा है यानी एडिशन और अल्ट्रेशन किया जा रहा है। बंगले की मरम्मत के प्रोजेक्ट को देखकर यह नहीं लगता कि इसकी मरम्मत की जा रही है बल्कि सच्चाई यह लगती है कि पूरे बंगले को तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है। यह भी आश्चर्य की बात है कि दिल्ली अर्बन आर्ट कमिशन ने नवंबर में आपत्ति करते हुए इस बंगले की मरम्मत को मंजूर करने से मना कर दिया है जबकि लोक निर्माण विभाग मंजूरी से पहले ही 17 अक्टूबर को वर्क अवार्ड कर चुका है। जनता यह जानना चाहती है कि क्या अब दिल्ली अर्बन आर्ट कमिशन की आपत्तियों को दूर कर दिया गया है या फिर उसे अनदेखा करके यह काम किया जा रहा है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो यह गैरकानूनी भी होगा।

संदेश *दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने नागरिकों को जागरुकता संदेश देने के लिए दो जनसंपर्क वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।* ***छाया: वैभव***

पौधारोपण पर्यावरण मंत्री गोपाल राय करेंगे पौधारोपण अभियान की शुरुआत

26 जून से 11 जुलाई तक वन महोत्सव का आयोजन करेगी सरकार: मंत्री गोपाल राय

नई दिल्ली (एजेंसी)।

दिल्ली सरकार 26 जून से 11 जुलाई तक 'वन महोत्सव' का आयोजन करेगी। पौधारोपण अभियान की शुरुआत पर्यावरण मंत्री गोपाल राय करेंगे। इस बाबत गोपाल राय ने कहा कि मेगा वृक्षारोपण अभियान में दिल्ली के सभी कैबिनेट मंत्री, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, सभी विधायक, गैर सरकारी संगठन और आरडब्ल्यूए भाग लेंगे। 27 जून को सभी 70 विधानसभाओं में विधायक, 28 जून को उपमुख्यमंत्री, 30 जून को स्वास्थ्य मंत्री, 2 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष, 5 जुलाई को परिवहन मंत्री, 7 जुलाई को खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री और 9 जुलाई को समाज कल्याण मंत्री पौधारोपण करेंगे। सरकार ने इस साल पूरी दिल्ली में 33 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। कोई भी व्यक्ति दिल्ली सरकार की 14 नर्सरी से मुफ्त पौधे ले सकता है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार 26 जून से 11 जुलाई तक 'वन महोत्सव' आयोजित करने का निर्णय लिया है।

सरकार की 14 नर्सरी में मुफ्त मिलेंगे औषधीय पौधे

गोपाल राय ने बताया कि इस पूरे साल में वृक्षारोपण अभियान के तहत 33 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

विश्व पर्यावरण दिवस पर सरकार ने औषधीय पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है। सरकार की पूरी दिल्ली में 14 नर्सरी हैं। दिल्ली का कोई भी व्यक्ति दिल्ली सरकार की नर्सरी में जा सकता है और मुफ्त में औषधीय पौधे प्राप्त कर सकता है। दिल्ली सरकार की नर्सरी में जो औषधीय पौधे उपलब्ध हैं, उसमें आंवला, अमरूद, अर्जुन, जामुन, नीम, तुलसी ,गिलोय ,एलोवेरा कढ़ी पत्ता इत्यादि शामिल हैं।

यमुना बैंक के गढ़ी मांडू से होगी अभियान की शुरुआत

गोपाल राय ने कहा कि इस 'वन महोत्सव अभियान' की शुरूआत 26 जून को यमुना बैंक के किनारे गढ़ी मांडू से की जाएगी। पौधारोपण के इस वृहद अभियान की शुरूआत पर्यावरण मंत्री गोपाल राय करेंगे। इसके बाद 27 जून को दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाएगा। 28 जून को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस अभियान में शिरकत करेंगे।

केजरीवाल सरकार ने यमुना को टैम्स बनाने का दावा कर उसे गंदा नाला बना डाला: आदेश गुप्ता

नई दिल्ली (एजेंसी)।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि कल-कल बहेगी यमुना का दावा करने वाले मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के शासन में यमुना पहले से ज्यादा मैली हो गई है। गुप्ता ने कहा कि साल 2015 में दिल्ली को लंदन और यमुना को टैम्स जैसी साफ बनाने का दावा करने वाले केजरीवाल अब यमुना को साफ करने की बात भी नहीं करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यमुना को साफ बनाने के नाम पर केजरीवाल सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन आज भी स्थिति यह है कि यमुना का पानी पीने तो क्या नहाने लायक भी नहीं है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने साल 2018-21 के दौरान यानि सिर्फ 3 सालों में दरियागंज के डॉ. सेन नाले की सफाई पर ही 200 करोड़ रुपए का खर्च दिखाया है, लेकिन वास्तविकता देखते ही बनती है। इस जगह यमुना गंदे नाले का एक रुप ले चुकी है और उसमें इतनी गंदगी है कि पास खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है। आदेश गुप्ता ने कहा कि इस तरह स्पष्ट है कि केजरीवाल सरकार यमुना की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए सिर्फ दिखावे के लिए दिखा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल और उनके मंत्री एवं विधायक यमुना की सफाई का नाम लेकर सरकारी पैसा लूट रहे हैं और इस लूटे हुए पैसे से केजरीवाल दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी का प्रचार करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल में वर्ष 2020-2021 में केजरीवाल सरकार ने 152 करोड़ रुपए यमुना की सफाई में खर्च दिखाया है।

संपादकीय

टीके से जुड़े कई किंतु-परंतु

कोविड-19 टीका खरीद और आपूर्ति नीति में सरकार ने जो आंशिक बदलाव किए हैं, उनसे यह आशा जगी है कि देश में चल रहा टीकाकरण अभियान अब कुछ हद तक पटरी पर लौट आएगा। चुनौतियों की शुरुआत 1 मई से हुई, जब 18 से 44 उम्र के वयस्कों के लिए टीकाकरण शुरू किया गया। उस दिन से मूल्य-निर्धारण को उदार बनाते हुए एक नई कोविड-19 टीकाकरण नीति लागू की गई। नए आयु-वर्ग को टीकाकरण से जोड़ने से लक्षित आबादी तीन गुना बढ़ गई, जबकि टीके की आपूर्ति पहले जैसी रही। केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र के लिए टीके की तीन अलग-अलग कीमतंर तय की गईं। उत्पादन में से आधे टीकों की खरीद की जिम्मेदारी राज्यों और निजी क्षेत्र को सौंप दी गई। टीका बनाने वाली कंपनियों द्वारा केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र के लिए 50-25-25 प्रतिशत का फॉर्मूला बनाकर टीके की आपूर्ति की जाने लगी। 18 से 44 वर्ष आयु-वर्ग के टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक करने हेतु 'को-विन' एप पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बना दिया गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और राज्य सरकारों ने फौरन ही नई रणनीति में कई तकनीकी खामियां बताईं। पहला तर्क दिया गया कि दशकों से चल रहे बच्चों के टीकाकरण अभियान से लेकर पोलियो उन्मूलन तक केंद्र सरकार ही हमेशा टीके खरीदती रही है। चूंकि राज्यों को खरीद का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए महामारी के मध्य में यह प्रयोग सही नहीं होगा। बाजार आधारित दृष्टिकोण अपनाने और राज्यों को एक-दूसरे से टीके खरीदने में प्रतिस्पर्द्धा करने का मतलब यह था कि केंद्र द्वारा इकट्ठे खरीद की तुलना में टीकों पर कुल सरकारी खर्च करीब तीन गुना बढ़ जाएगा। इससे टीकों की उपलब्धता भी प्रभावित होगी, क्योंकि गरीब प्रदेशों की तुलना में संपन्न राज्य टीकों को अपने लिए कहीं अधिक सुरक्षित रख सकते हैं। इन्हीं सारी वजहों से विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि महामारी में सभी नागरिकों के लिए टीके मुफ्त होने चाहिए और दुनिया के तमाम देशों की तरह भारत में भी टीकों की खरीद की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को निभानी चाहिए। बहरहाल, 1 मई को नई नीति के लागू होते ही टीकाकरण अभियान लगभग बेपटरी हो गया। सभी आयु-वर्ग के लिए टीके की कमी हो गई और अपनी दूसरी खुराक की प्रतीक्षा करने वाले लोगों का इंतजार लंबा होता गया। टीके की आपूर्ति एक बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती से पार पाने के लिए करीब 12 राज्यों ने ग्लोबल टेंडर, यानी वैश्विक निविदाएं जारी कीं, पर टीका बनाने वाली कंपनियों की तरफ से उन्हें यही जवाब मिला कि वे केंद्र सरकार से ही खरीद संबंधी समझौता करेंगी। इसके बाद, कई मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उनके लिए टीके खरीदने और सामान्य दर पर या मुफ्त में उन्हें मुहैया कराने को कहा। नई नीति से निजी अस्पतालों के पास भी जरूरत से अधिक टीके हो गए, जबकि सरकारी अस्पतालों में इसकी कमी हो गई। नतीजतन, टीकाकरण अभियान धीमा पड़ता गया, और कई राज्यों ने 18-44 वर्ष वालों के लिए टीकाकरण बंद कर दिया। ऐसे में, सर्वोच्च न्यायालय ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया और टीकाकरण नीति को 'मनमाना व तर्कहीन' बताया। 'को-विन' पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन भी एक चुनौती थी, जिसने इंटरनेट सुविधा वाले मोबाइल या कंप्यूटर न रखने वाले एक बड़े तबके को टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया था। आखिरकार 7 जून को केंद्र ने टीकाकरण नीति में बदलाव किया। अब केंद्र सरकार ही टीके की कुल उपलब्धता का 75 फीसदी हिस्सा खरीदेगी और उसका मूल्य चुकाएगी। राज्यों को टीकाकरण के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। सरकारी अस्पतालों में पहले की तरह टीके मुफ्त में मिलेंगे, जबकि निजी अस्पतालों में भी सेवा-शुल्क को अधिकतम 150 रुपये तय कर दिया गया है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि मुफ्त टीकाकरण करके सरकार ने कोई उदार रवैया दिखाया है। भारत में हमेशा से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में टीकाकरण सहित सभी रोग-निरोधी स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क रही हैं। इसीलिए, केंद्र का मुफ्त में कोविड-19 टीकाकरण का दावा गले नहीं उतरता। अतीत की तरह इस बार भी उसने टीकाकरण की अपनी जिम्मेदारी ही स्वीकार की है। इस समय देश में सक्रिय कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों की कुल संख्या में निजी क्षेत्र की भागीदारी महज चार फीसदी है, जबकि उसे 25 फीसदी टीका आवंटित किया गया है। इस वजह से निजी केंद्रों पर टीकाकरण की उपलब्धता जरूरत से अधिक है और सरकारी केंद्रों पर लोग टीकों के लिए भटक रहे हैं। चूंकि आने वाले हफ्तों में टीके का उत्पादन बढ़ने की पूरी संभावना है, इसलिए अच्छी रणनीति यही होगी कि सभी टीकाकरण केंद्रों के अनुपात के अनुसार (लगभग पांच प्रतिशत) निजी क्षेत्र को टीके आवंटित किए जाएं। ऐसा करने पर सरकारी केंद्रों पर टीके की उपलब्धता और रफ्तार, दोनों में पर्याप्त सुधार आ सकता है। दुनिया भर के तमाम देशों में लोगों को कोविड टीके के लिए एक पैसा भी नहीं देना पड़ता, चाहे वे निजी केंद्र से ही क्यों न अपने टीके लगवाएं। अगर भारत भी अपने अभियान को वास्तव में मुफ्त कहना चाहता है, तो इसे भी वही रणनीति अपनानी चाहिए। केंद्र सरकार को टीका बनाने वाली कंपनियों से शत-प्रतिशत खरीदारी करने और निजी क्षेत्र के साथ उसे साझा करने के बारे में भी सोचना चाहिए (जैसा कि जनवरी से अप्रैल तक किया गया था), साथ ही, निजी केंद्रों के सेवा-शुल्क का भुगतान भी आम लोगों के बजाय सरकार करे, तभी ये टीके वास्तव में निःशुल्क कहे जा सकेंगे। बेशक टीके की आपूर्ति और नीतियों से जुड़े कुछ मसलों को हल कर दिया गया है, लेकिन यह समय केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा टीके के वितरण और टीकाकरण की प्रक्रियागत दिक्कतों को दूर करने का भी है। हमें अपने देश में अगले छह-आठ महीने के लिए कोविड-19 टीकाकरण का एक विस्तृत रोडमैप बनाना होगा और टीके की आपूर्ति-श्रृंखला को भी दुरुस्त करना होगा। वैक्सीन की कमी से निपटने के लिए साक्ष्य-आधारित संचार रणनीति बनाने और उसे लागू करने की जरूरत है। टीकाकरण नीति में बदलाव सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन अब भी काफी कुछ किया जाना शेष है। सरकारों को यह सुनिश्चित करना ही होगा कि बिना किसी मुश्किल के हर नागरिक को टीका लग पाए। भारत ऐसा पहले कर पाया है, इस बार भी जरूर कर पाएगा।

प्रवीण कुमार सिंह

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ तालमेल बैठाने में ट्विटर मर्यादा में रहे

संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की यह साझा जिम्मेदारी है। ऐसे में कोई नागरिक या संस्थान ट्विटर को इन संस्थाओं से ऊपर कार्य करने की इजाजत नहीं देगा कि वह देश में मूल स्वतंत्रता प्रदान करने वाला सर्वोच्च निकाय बन जाए। उम्मीद है कि दुनिया के सबसे बड़े और गतिशील लोकतंत्र के साथ तालमेल बैठाने में ट्विटर खुद को मर्यादा में रखेगा। उसे इस गलतफहमी से निकलना होगा कि वह भारतीय गणतंत्र की जगह ले सकता है। यदि वह इस बुनियादी सच्चाई को नहीं समझता तो फिर उसे कड़ाई से इसे समझना होगा।

आखिरकार ट्विटर सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल एथिक्स कोड) नियमों के अनुपालन को लेकर तैयार होता दिख रहा है। देखना है कि वह अनुपालन सही तरह करता है या नहीं? यह सवाल इसलिए, क्योंकि वह लगातार दोहरे रवैये का परिचय दे रहा है। उसकी हरकतों को देश के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप भी कहा जा सकता है। ट्विटर के रवैये में बदलाव के पीछे भारत सरकार की उस अंतिम चेतावनी को भी एक वजह माना जा रहा है, जिसमें सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि नए नियमों को न मानने पर ट्विटर आपराधिक जवाबदेही को लेकर विधिक संरक्षण गंवा सकता है। ट्विटर की हीलाहवाली का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इस साल फरवरी में ही नए नियम बन जाने के बाद भी उसने अपेक्षित अनुपालन की दिशा में कदम नहीं बढ़ाए। निःसंदेह माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर एक वैश्विक दिग्गज है, जिसकी हैसियत कई देशों की जीडीपी से भी बड़ी है, लेकिन शायद इसी खुमारी में उसने यह गफलत पाल ली कि वह भारतीय गणराज्य से भी बड़ा है। उसके रवैये पर अदालत में एक याचिकाकर्ता ने यह सवाल उठाया कि नए नियमों के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह अधिकार है कि वह ट्विटर पर किसी अपमानजनक, असत्य और फर्जी ट्वीट के खिलाफ स्थानीय शिकायत अधिकारी के समक्ष आपत्ति जता सकता है, क्योंकि ट्विटर एक महत्वपूर्ण इंटरनेट मीडिया माध्यम है, लेकिन वह अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाए, क्योंकि ट्विटर ने ऐसा कोई अधिकारी नियुक्त ही नहीं किया था। दिल्ली पुलिस ने भी यह रेखांकित किया कि जब उसने

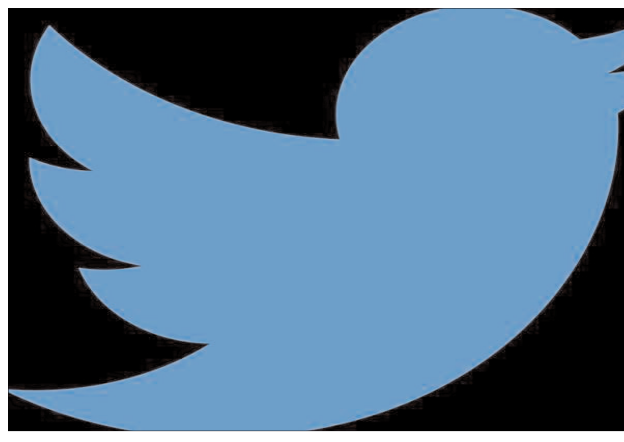

टूलकिट मामले की जांच शुरू की तो ट्विटर ने ऐसा व्यवहार किया, मानों वही जांच संस्था और निर्णायक प्राधिकारी हो।

हाल में ट्विटर ने दावा किया कि महामारी के दौरान जनसंवाद और लोगों तक मदद पहुंचाने में उसने एक प्रभावी माध्यम की भूमिका निभाई और वह जनसेवा की राह में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मंडराते खतरे को लेकर चिंतित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि तमाम अन्य क्षेत्रों में तकनीकी तरक्की की तरह सोशल नेटवर्क मंचों की उपयोगिता भी असंदिग्ध है। उन्होंने मानवीय संवाद को क्रांतिकारी बना दिया है, लेकिन क्या इसकी आड़ में उन्हें मनमानी करने की छूट दी जा सकती है?

नए आइटी नियमों पर अपने जवाब में ट्विटर ने कहा कि वह भारत की जनता के लिए बेहद प्रतिबद्ध है और देश-दुनिया के नागरिक समाज के साथ नए आइटी नियमों के मूल तत्वों को लेकर चिंतित है। उसका दावा है कि इन नियमों से जुड़े कुछ पहलू स्वतंत्र एवं खुले सार्वजनिक संवाद की राह बाधित करने वाले हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर की इन खोखली दलीलों की धज्जियां उड़ाकर रख दीं।

उन्होंने कहा कि सरकार खुद निजता का सम्मान करती है, लेकिन जहां तक वाक् स्वतंत्रता की बात है तो उस पर ट्विटर की अपनी नीतियां ही अस्पष्ट हैं। वह मनमाने ढंग से लोगों के अकाउंट बंद करता है, ट्वीट डिलीट करता है। एक चैनल ने ट्विटर की ऐसी मनमानी और दोहरे रवैये के सुबूत भी दिए। इस चैनल ने गर्भपात के अधिकार के आलोक में महिला अधिकारों पर एक कार्यक्रम केवल डिजिटल मीडिया के लिए प्रसारित किया। ट्विटर ने उसे फिल्टर कर दिया। दस मिनट के उस वीडियो में प्रतिगामी कानूनों को रद करने और महिलाओं को विकल्प देने को लेकर तर्क दिए गए थे। ट्विटर ने उसे संवेदनशील सामग्री करार देकर चैनल की पहुंच को सीमित कर दिया। परिणामस्वरूप चैनल की इंटरनेट मीडिया टीम दर्शकों की प्रतिक्रिया नहीं जान सकी। ऐसे में एक बड़ा सवाल यही है कि क्या गर्भपात पर संवाद संवेदनशील सामग्री की श्रेणी में आता है?

आइटी विशेषज्ञ जितिन जैन का कहना है, 'ट्विटर एक कॉरपोरेट बोर्ड रूम से वैश्विक सामग्री से जुड़े विमर्श को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। सामग्री को लेकर उसका निर्णय अक्सर अस्पष्ट और नीतिगत विरोधाभासों एवं दोहरे रवैये से परिपूर्ण होता है। प्रायः यह दीर्घकालिक नीति और सिद्धांतों के बजाय राजनीतिक परिवेश से प्रेरित होता है। 'यह वास्तव में एक गंभीर आरोप है और ट्विटर को अपने कृत्यों को लेकर पारदर्शिता बढ़ानी होगी। साथ ही उपदेश देने से भी बाज आना चाहिए। वह दावा करता है कि जनता के हितों को सुरक्षित रखना जनप्रतिनिधियों, उद्योगों और नागरिक समाज की साझा जिम्मेदारी है। ऐसा कर उसने खुद को जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों और भारतीय नागरिक समाज के समकक्ष ला खड़ा किया है। यह बिल्कुल दायरे से बाहर वाली बात है।

कोई भी कंपनी चाहे वह देसी हो या विदेशी-बहुराष्ट्रीय, सरकार के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकती, जिसे जनता का जनादेश प्राप्त होता है। न ही वह खुद को भारत के नागरिक समाज वाले पाले में खड़ा कर सकती है। ट्विटर के दुराग्रह और हठ ने भारत सरकार को तल्ख प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाने का काम किया। सरकारी बयान में कहा गया, 'ट्विटर फिजूल की बातें बंद कर कानूनों का अनुपालन करे। विधि निर्माण और नीतियों का खाका बनाना संप्रभु राष्ट्र का अधिकार है और ट्विटर महज एक इंटरनेट मीडिया मंच है और उसे यह बिल्कुल हक नहीं कि वह बताए कि भारत का विधिक नीतिगत ढांचा कैसा होना चाहिए...।' भारत में शायद ही कोई सरकार किसी कंपनी को लेकर इतनी तल्ख प्रतिक्रिया दे। जहां तक नागरिकों के हितों की सुरक्षा का सवाल है तो ट्विटर यह अवश्य जान ले कि न तो देश के संविधान और न ही जनता ने यह दायित्व किसी व्यक्ति या कंपनी को सौंपा है।

संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की यह साझा जिम्मेदारी है। ऐसे में कोई नागरिक या संस्थान ट्विटर को इन संस्थाओं से ऊपर कार्य करने की इजाजत नहीं देगा कि वह देश में मूल स्वतंत्रता प्रदान करने वाला सर्वोच्च निकाय बन जाए। उम्मीद है कि दुनिया के सबसे बड़े और गतिशील लोकतंत्र के साथ तालमेल बैठाने में ट्विटर खुद को मर्यादा में रखेगा। उसे इस गलतफहमी से निकलना होगा कि वह भारतीय गणतंत्र की जगह ले सकता है। यदि वह इस बुनियादी सच्चाई को नहीं समझता तो फिर उसे कड़ाई से इसे समझना होगा।

मलाईदार पद का सुख भोग रहा कर्मचारी कभी भी नहीं चाहता आए तबादलों का मौसम

एक फिल्मी गीत है- पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, पांचवां मौसम प्यार का, इंतजार का! लगता है कि गीतकार ने छठे, सातवें आदि मौसमों का चुनाव श्रोताओं की पसंद पर छोड़ दिया है। किसी नेता से पूछिए तो वह इस सूची में चुनावी मौसम को जरूर शामिल करवाना चाहेगा, ताकि जहां मन हो या मलाई हो, वहां ट्रांसफर हुआ जा सके। वैसे अब वह चुनाव बाद भी अपने ट्रांसफर का जुगाड़ कर लेते हैं। उनकी चले तो वे पालाबदल को भी तबादला नाम देना पसंद करें।

जहां तक सरकारी कर्मचारियों का ताल्लुक है, उनके लिए तबादलों के मौसम से बढ़कर खट्टा-मीठा अन्य कौन सा मौसम होगा? जिस तरह निर्वाचित विधायक अथवा सांसद नहीं चाहता कि मध्यावधि चुनाव की नौबत आए, उसी तरह मलाईदार पद का सुख भोग रहा कर्मचारी भी नहीं चाहता कि तबादलों का मौसम आए, भले ही मानसून कुछ लेट हो जाए या जल्दी आ जाए। इसके विपरीत किसी सूखे पद पर कांटे की तरह सूख रहा कर्मचारी सपने में भी तबादला सूची में अपना नाम मनचाही पोस्टिंग के साथ सबसे ऊपर उसी तरह देखता है, जिस तरह चुनाव में हारा हुआ प्रत्याशी अगले चुनाव में अपने जीतने की कामना करता है या फिर दूसरे दल में अपने लिए मलाई देखता है। आमतौर पर तबादलों का मौसम सरकार बदलते ही या फिर गर्मियों के जोर पकड़ते ही शुरू हो जाता है और मानसून के आगमन तक जारी रहता है। दरअसल आंधी के मौसम में ही तबादलों की आंधी आती है। इस मौसम में चलने वाली तबादलों की आंधी में जोड़-तोड़ के गुणों से युक्त वही भद्रजन रूपी पेड़ मनचाहे स्थान पर कायम रह पाते हैं, जिनकी जड़ें दूर सत्ता के गलियारों या फिर साहब के बंगलों तक फैली होती हैं अथवा जो पत्र-पुष्प का आदान-प्रदान करने में निपुण होते हैं।

तबादलों के मौसम में कर्मचारियों के स्वास्थ्य की तो पूछिए ही मत! रात को सपने में भी कोई उन्हें उठाकर दूर-दराज के इलाके में जा पटकता है। दफ्तर में काम करते वक्त उन्हें अपने फेफड़ों तक आक्सीजन ट्रांसफर करने में भी खासी दिक्कत महसूस होती है। मन किसी भी फाइल में नहीं रमता। वे दिन भर बेचैन होकर इधर-उधर की खबरें सूंघते फिरते हैं। तबादलों की चर्चा चलते ही उनमें अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होने लगता है। इस मौसम के आते ही कर्मचारियों की सामान्य बोलचाल की भाषा में कुछ नए शब्द शामिल हो जाते हैं। मसलन- नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, म्यूचुअल ट्रांसफर, कपल केस, कंपलेंट बेसिस, मेडिकल ग्राउंड आदि-आदि। जैसे क्रिकेट मैच के दौरान लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि स्कोर क्या हुआ, वैसे ही तबादलों के मौसम में कर्मचारी एक दूसरे से पूछते हैं- लिस्ट आ गई क्या? ट्रांसफर फोबिया ग्रस्त कर्मचारी को पंकज उधास की मशहूर गजल आइए बारिशों का मौसम है, इन दिनों चाहतों का मौसम है, भी कुछ यूं सुनाई देती है - आइए तबादलों का मौसम है, इन दिनों सिफारिशों का मौसम है। तबादलों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव शोध का विषय भी हो सकता है। जिस तरह अधिकतर कर्मचारी अपनी तनख्वाह का एक निश्चित भाग एलआइसी, जीपीएफ, पीपीएफ आदि विभिन्न मदों में डालते हैं, उसी प्रकार जो कर्मचारी आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हुए या यूं कहिए कि जिनका जाब ट्रांसफरेबल है, वे हर महीने कुछ धनराशि अपने अघोषित ट्रांसफर अकाउंट में जमा करते रहते हैं, ताकि तबादलों के इस मौसम में चलने वाली आंधी से बचने का उपाय कर सकें। शायद भगवान भी सोचता होगा कि भूलोक का यह नादान प्राणी जितना यत्न तन-मन-धन से अपने ट्रांसफर के लिए कर रहा है, उसका थोड़ा-सा हिस्सा भी यदि मुझे याद करने में लगाता तो मैं उसे इस भवसागर से ही पार लगा देता, लेकिन ट्रांसफरेबल जाब वाले प्राणी को लगता है कि भगवान इस संसार से तो चाहे मुक्ति दिला दें, लेकिन सरकारी नौकरी में मनचाही पोस्टिंग के लिए ट्रांसफर आर्डर दिलवाना शायद उनके भी बस की बात नहीं!

डेल्टा वैरिएंट ने बढ़ाई फिक्र

कोरोना वायरस का जो नया रूप दुनिया भर में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को चिंतित किए हुए है, वह है डेल्टा वैरिएंट। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) ने इसे वैरिएंट ऑफ कंसर्न यानी वायरस का चिंताजनक रूप कहा है। वैसे तो यह कई देशों में मौजूदगी दर्ज करा चुका है, लेकिन ब्रिटेन तो जैसे इसकी गिरफ्त में आ चुका है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड (पीएचई) के आंकड़ों के मुताबिक, वहां इकट्ठा किए जा रहे सैंपल्स में 61 फीसदी मामले डेल्टा वैरिएंट के ही हैं। इसका मतलब यह है कि वहां पिछले साल गदर मचा देने वाले अल्फा वैरिएंट से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में डेल्टा वैरिएंट आ गया है। ध्यान रहे किसी वैरिएंट को चिंताजनक श्रेणी में तब डाला जाता है, जब उसकी बढ़ी हुई संक्रामक क्षमता और मरीज को अस्पताल ले जाने की बढ़ी हुई जरूरत के सबूत उपलब्ध हों। इन दोनों ही मोर्चों पर इसकी मजबूती इसे न केवल इंग्लैंड जैसे देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के स्तर पर खतरनाक बनाती है। गौर करने की बात यह भी है कि मामला डेल्टा वैरिएंट तक ही सीमित नहीं रहा। इसका और परिष्कृत रूप भी आ गया है जिसे डेल्टा प्लस कहा जा रहा है।

भारत में अभी इसके मरीजों की संख्या ज्यादा नहीं है, बावजूद इसके महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने चेताया है कि यही डेल्टा प्लस वैरिएंट कोरोना महामारी की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। स्वाभाविक रूप से सरकार ने स्वास्थ्य ढांचे को इसके लिए तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है, लेकिन एक तो ऐसी सारी कवायद की आखिरी परीक्षा लहर आने के बाद ही होती है। तभी यह पता लगता है कि सरकार के निर्देश किस हद तक जमीन पर उतरे और दरअसल उसका कितना फायदा प्रभावित लोगों तक पहुंचाया जा सका।

मगर उससे ज्यादा जरूरी है खुद को बार-बार याद दिलाना कि वायरस के खिलाफ यह जंग लड़ना और जीतना अकेले सरकार के बूते की बात है ही नहीं। यह लड़ाई तभी जीती जा सकती है, जब एक-एक नागरिक पूरी जागरूकता, सावधानी और शिद्दत से इसमें भागीदारी करे। विशेषज्ञों के मुताबिक अब तक के ऑब्जर्वेशन से यह स्पष्ट है कि वैक्सीन इस वैरिएंट पर भी कारगर हैं। अपने यहां वैक्सिनेशन अभियान में आई थोड़ी सुस्ती इस संदर्भ में चिंता की एक अतिरिक्त बात हो सकती है, लेकिन ताजा प्रयासों की बदौलत उम्मीद है कि यह अभियान जल्दी ही जोर पकड़ेगा। ऐसे में आम लोगों का सहयोग दो स्तरों पर निर्णायक साबित हो सकता है। एक तो यह कि टीका लगवाने को लेकर उदासीनता हर हाल में जल्द से जल्द खत्म की जाए और दूसरा, अनलॉक के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में वैसी लापरवाही बिल्कुल न हो, जैसी पहली लहर के उतार के बाद दिखाई गई थी।

किसान उन गलतियों से सीखने को तैयार नहीं, जिनके चलते खेती बदहाली का शिकार बनी

नकदी फसलों की बिक्री के लिए सरकार उत्पाद विशेष के लिए पोर्टल बना रही है। जैसे मधुमक्खी पालकों को शहद का सही दाम दिलाने के लिए मधु क्रांति पोर्टल और हनी कार्नर की शुरुआत की गई है। यह पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म का काम करेगा। सरकार ने वन डिस्टिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट के लिए देश भर के 728 जिलों में कृषि, बागवानी, पशु, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन और जलीय कृषि हेतु उत्पादों की पहचान की है। इसके तहत देश 226 जिलों में फल, 40 जिलों में धान, 107 जिलों में सब्जियां और 105 जिलों में मसालों की खेती को बढ़ावा देकर दुनिया भर में ब्रांडिंग की जाएगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ कृषि निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी।

एक ओर जब कुछ किसान संगठन कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज करा रहे हैं तो दूसरी ओर देश में गेहूं की रिकार्ड सरकारी खरीद हो रही है। अब तक 44.4 लाख किसानों से 76,000 करोड़ रुपये का गेहूं खरीदा जा चुका है। गेहूं खरीद की यह रकम बिना किसी बिचौलियों के सीधे किसानों के खातों में पहुंची है। जहां गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर हो रही है, वहीं खुले बाजार में सरसों की कीमतें रिकार्ड बना रही हैं। कई मंडियों में सरसों 8,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिकी है, जबकि सरसों का एमएसपी 4650 रुपये प्रति क्विंटल है। गेहूं और सरसों की खरीद-बिक्री के बनते रिकार्ड को देखें तो कुछेक किसान संगठनों द्वारा तीनों कृषि कानूनों का विरोध बेमानी ही लगता है। किसान आंदोलन राजनीतिक विरोध में तब्दील। किसान संगठन अब कृषि कानूनों के विरोध से आगे बढ़कर भाजपा को हराने की मुहिम में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में राकेश टिकैत ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर उनसे समर्थन मांगा। वह खुलेआम कह रहे हैं कि बंगाल को अब पंजाब और उत्तर प्रदेश में दोहराना है। साफ है किसान आंदोलन राजनीतिक विरोध में तब्दील हो चुका है। यही कारण है कि आम किसानों ने इस आंदोलन से दूरी बना ली है। आंदोलन करने वाले किसान संगठन उन गलतियों से सबक सीखने को तैयार नहीं हैं, जिनके चलते खेती-किसानी बदहाली का शिकार बनी।

भारतीय खेती की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि सरकारों का पूरा जोर दूरगामी महत्व वाले निवेश पर न होकर सब्सिडी देने पर रहा। यह सब्सिडी भी चुनिंदा क्षेत्रों-फसलों पर केंद्रित रही। इसका नतीजा यह निकला कि विविध फसलों की खेती करने वाला भारतीय किसान चुनिंदा फसलों की खेती में उलझकर रह गया। हरित क्रांति रूपी एकांगी कृषि विकास से शुरू में तो खेती में खुशहाली आई, लेकिन जल्दी ही उसकी सीमाएं प्रकट होने लगीं। विडंबना यह रही कि सरकारों ने हरित क्रांति की इन खामियों को दूर न करके सब्सिडी, मुफ्त बिजली-पानी, कर्जमाफी जैसे चुनावी पासें फेंकना शुरू कर दिया जिससे समस्या और गंभीर हुई। इस प्रकार धीरे-धीरे खेती-किसानी घाटे के सौदे में तब्दील हो गई।बदहाली के दुष्चक्र के फंसी खेती-किसानी को उबारने के लिए कृषि विशेषज्ञ लंबे समय से सुझाव दे रहे हैं कि विविधीकृत फसल प्रणाली अपनाई जाए, लेकिन गेहूं-धान केंद्रित फसल चक्र को तोड़ना आसान नहीं था। खेती-किसानी की इन्हीं खामियों को दूर करने और कृषि के आधुनिकीकरण के लिए मोदी सरकार ने तीन नए कृषि कानून बनाया। दुर्भाग्यवश गेहूं-धान की एकफसली खेती करने वाले किसानों और इनकी खरीद-बिक्री से जुड़े बिचौलियों की ताकतवर लॉबी को ये सुधार रास नहीं आ रहे हैं। इन कानूनों के जरिये सरकार सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ऐसी व्यवस्था बना रही है, जहां किसान अपनी मर्जी से अपनी फसल कहीं भी बेच सकेंगे। किसानों को उपज की वाजिब कीमत मिलने से न सिर्फ खेती-किसानी फायदे का सौदा बनेगी, बल्कि पढ़े-लिखे लोग भी खेती करेंगे, जिससे गांवों में रोजगार के अवसर निकलेंगे। इससे शहरों की ओर होने वाले पलायन में भी कमी आएगी।

किसान नेता कुछ भी कहें, सरकार का पूरा जोर कृषि के विविधीकरण पर है। इससे न सिर्फ फसल चक्र का पालन होगा, बल्कि गेहूं-धान की एकफसली खेती से भी मुक्ति मिलेगी। सरकार इससे परिचित है कि केवल खेती से किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल नहीं होगा। इसीलिए वह कृषि एवं ग्रामीण जीवन में आयपरक गतिविधियों को शामिल कर रही है। किसानों को उनकी उपज की लाभकारी कीमत दिलाने के लिए सरकार ने गन्ने के साथ-साथ गेहूं, चावल, मक्का और दूसरे खाद्यान्नों से भी एथनॉल उत्पादन को मंजूरी दे दी है। इससे न सिर्फ अतिरिक्त अनाज की खपत हो जाएगी, बल्कि पेट्रोलियम के आयात पर निर्भरता घटाने में भी मदद मिलेगी। सरकार की एथनॉल नीति को अभूतपूर्व कामयाबी मिली है। 2014 में जहां 38 करोड़ लीटर एथनॉल की खरीद हो रही थी, वहीं अब हर साल 320 करोड़ लीटर एथनॉल खरीदा जा रहा है।

पिछले साल पेट्रोलियम कंपनियों में 21,000 करोड़ रुपये का एथनॉल खरीदा और इसका अधिकांश हिस्सा किसानों की जेब तक पहुंचा। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिलाने के लक्ष्य को पांच साल पहले अर्थात 2030 के बजाय 2025 कर दिया है। दालों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के बाद अब सरकार तिलहनों के घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर फोकस कर रही है। सरकार बांस की खेती को भी बढ़ावा दे रही है। इसी तरह औषधीय पौधों अश्वगंधा, सहजन, शतावरी, मशरूम, स्ट्राबेरी, आंवला की खेती को प्रोत्साहन दे रही है। इन औषधीय पौधों के कम उत्पादन के कारण किसानों को अच्छी कीमत मिलती है। इनकी खेती से न सिर्फ किसानों को लगातार आमदनी होती रहेगी, बल्कि गांवों में इनके प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन का नेटवर्क बन जाएगा, जिससे रोजगार के भरपूर अवसर निकलेंगे। नकदी फसलों की बिक्री के लिए सरकार उत्पाद विशेष के लिए पोर्टल बना रही है। जैसे मधुमक्खी पालकों को शहद का सही दाम दिलाने के लिए मधु क्रांति पोर्टल और हनी कार्नर की शुरुआत की गई है। यह पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म का काम करेगा। सरकार ने वन डिस्टिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट के लिए देश भर के 728 जिलों में कृषि, बागवानी, पशु, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन और जलीय कृषि हेतु उत्पादों की पहचान की है। इसके तहत देश 226 जिलों में फल, 40 जिलों में धान, 107 जिलों में सब्जियां और 105 जिलों में मसालों की खेती को बढ़ावा देकर दुनिया भर में ब्रांडिंग की जाएगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ कृषि निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

सांसद मेनका गांधी का कथित ऑडियो वायरल, आगरा के पशु चिकित्सक से जुड़ा मामला, जांच शुरू

आगरा । सांसद मेनका गांधी का कथित आडियो आगरा के पशु चिकित्सक से जुड़ा है। इसकी जानकारी होने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी प्रभु एन. सिंह के आदेश पर पशु चिकित्सक की जांच शुरू कर दी गई है। न सिर्फ पशु चिकित्सक की डिग्री बल्कि उनके क्लीनिक की जांच की जाएगी। इधर, अभद्र भाषा के प्रयोग को लेकर पशु चिकित्सकों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। देशभर में आज पशु चिकित्सक काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं और मेनका गांधी से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। पशु चिकित्सक को हड़काने वाला आडियो सांसद मेनका गांधी का बताया जा रहा है। यह आडियो बीते बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। गुरुवार सुबह पता चला कि यह आडियो आगरा के पशु चिकित्सक डा. एलएन गुप्ता से जुड़ा हुआ है। इस कथित आडियो में मेनका गांधी पशु चिकित्सक को एक श्वान का गलत इलाज करने पर हड़का रही हैं। उससे अपशब्द भी कहे हैं। पशु चिकित्सक ने अपनी सफाई देनी चाही लेकिन सांसद ने उसे हड़का दिया। आगरा के एमजी रोड किनारे पशु चिकित्सक का क्लीनिक है। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण जांच में जल्दी की जा रही है। जांच टीम में शामिल मुख्य पशु चिकित्साधिकारी वीएस तोमर का कहना है कि वायरल आडियो की जांच के मामले में पशु चिकित्सक से भी पूछताछ की जा रही है। जांच रिपोर्ट जल्द ही डीएम को सौंप दी जाएगी।

वाराणसी से लौट रही एंबुलेंस की चैनपुर में ट्रक से टक्कर, पांच लोग गंभीर रूप से घायल

चैनपुर (भभुआ) । कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी से लौट रही एंबुलेंस चैनपुर में ट्रक से टकरा गई। हादसा मरहियां हाटा मार्ग में ग्राम कुशहरियां नदी पुल के पास बुधवार रात करीब नौ बजे हुआ। वाराणसी से मरीज को लेकर लौट रही एंबुलेंस चावल लदे ट्रक से टकरा गई। उक्त घटना में एंबुलेंस में बैठे मरीज सहित पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिनका इलाज दुर्गावती पीएचसी में कराया गया। जबकि एक को गंभीर अवस्था में वाराणसी रेफर किए जाने की बात बताई जा रही है। घायलों में ग्राम तिंवई के शोवित कुमार एवं शोभित के पिता रामदरस बिंद, चाचा शिवब्रत बिंद, मौसी कमलावती देवी ग्राम सुरहा थाना चांद के निवासी, जीजा राजन बिंद भभुआ थाना क्षेत्र के ग्राम बेतरी के निवासी शामिल हैं। घायल के परिजनों ने बताया कि शोवित कुमार का एक हाथ टूटा हुआ था। जिसका इलाज वाराणसी में चल रहा था। इलाज के दौरान हाथ में रॉड लगाया गया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के उपरांत बुधवार की रात नौ बजे के करीब मरहियां हाटा मार्ग से होते हुए सभी लोग ग्राम तिवई वापस लौट रहे थे। तभी कुशहरियां नदी पुल के समीप हाटा की तरफ से जा रहे चावल लदे ट्रक में एंबुलेंस टकरा गई। दुर्घटना इतनी जबरदस्त हुई कि एंबुलेंस का अगला हिस्सा बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया एवं उसमें बैठे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक, शोवित बिंद जिन का हाथ टूटा था उनके जबड़ा एवं सिर में गंभीर रूप से चोट लगी है। चाचा शिवव्रत बिंद एवं मौसी कमलावती देवी का सिर फटा है। जीजा राजन बिंद को मामूली चोट आई है, जबकि शोवित बिंद के पिता रामदरस बिंद को भी गंभीर चोट लगने की बात बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए तत्काल दुर्गावती पीएससी में लाया गया। जहां सभी का प्राथमिक उपचार हुआ। जिसके उपरांत गंभीर रूप से जख्मी शोवित बिंद को भभुआ सदर अस्पताल में रेफर किया गया। जहां से बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ट्रामा सेंटर में रेफर किए जाने के बाद बताई जा रही है।

तीन माह तक प्रभावित रहेगी भागलपुर में यातायात व्यवस्था, बरसात बाद होगा सड़क मरम्मत का कार्य

भागलपुर । शहर में जल आपूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। इस काम के लिए सड़कों को खोदा गया है। लिहाजा, यातायात की समस्या खड़ी हो रही है। वहीं, रूक-रूक कर जाम लग रहा है। इसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तीन माह और लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ सकता है। जल आपूर्ति के लिए पाइप बिछाने के काम पर मिट्टी के साथ ही सड़कों को भी खोद दिया गया है। इसके कारण सड़क की चौड़ाई सिमटकर छह से आठ फीट होने आवागमन समस्या खड़ी हो गई है। उस पर सात-आठ दिन तक लगातार बारिश के कारण सड़क पर कीचड़ होने से मुश्किलें और बढ़ा दी। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर बुडको ने तिलकामांझी और बरारी, तिलकामांझी और जीरोमाइल व तिलकामांझी और कचहरी चौक के बीच सड़क को मोटरेबल करने की दिशा में कार्य शुरू किया गया। ईंट डालने के बाद उसके उपर स्टोन डस्ट डालने के बजाय मिट्टी डालकर सड़क मोटरेबल करने के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। मिट्टी गिली होने के कारण कीचड़ होने से आवागमन की समस्या खड़ी हो रही है। बरारी रोड, जेल रोड व सैंडिस कंपाउंड से कचहरी चौक के बीच यातायात प्रभावित हो रहा है। दिनभर रूक-रूककर जाम लगने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर, सड़क की मरम्मत के लिए बुडको ने पथ निर्माण विभाग को सात करोड़ रुपये भुगतान कर दिया है, लेकिन विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बरसात के बाद ही सड़क की मरम्मत कराई जाएगी। बरसात में बिटुमिनस कराने पर सड़क ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसलिए कि पानी अलकतरा का दुश्मन होता है। बरसात में बिटुमिनस कार्य कराया जाएगा। ऐसी स्थिति में तीन माह और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता नवल किशोर सिंह ने कहा कि सड़क ओपीआरएमसी के तहत है। इसलिए टेंडर करने के बजाय ओपीआरएमसी के ठेकेदार से सड़क की मरम्मत कराई जाएगी। प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने पर बरसात के बाद बिटुमिनस कार्य कराया जाएगा।

पंजाब में हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की तैयारी, कैप्टन सरकार उठा सकती है बड़ा कदम

चंडीगढ़ । पंजाब के लोगों को जल्द ही बड़ा तोहफा मिल सकता है। राज्य की कांग्रेस सरकार सभी परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की तैयारी कर रही है। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार यह कदम उठाने की तैयारी में है। राज्य में महंगी बिजली से कांग्रेस घबराई हुई है और इसी कारण पार्टी हाईकमान की ओर से कैप्टन को दिए 18 बिंदु के कार्यों में मुफ्त बिजली प्रमुख रूप से शामिल है।

दरअसल पंजाब कांग्रेस की अंतर्कलह को खत्म करने के लिए कांग्रेस हाईकमान और राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को 18 प्वाइंट का एजेंडा दिया है। इन 18 प्वाइंटों में सबसे अहम हर घर को 200 यूनिट निशुल्क बिजली देना भी शामिल है। पंजाब में घरेलू सेक्टर की महंगी बिजली पिछले लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसको लेकर शहरी वर्ग में रोष व्याप्त है। 2017 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने आम लोगों से वादा किया था कि प्राइवेट थर्मल प्लांटों के साथ बिजली समझौते रद करके वह बिजली दरों में आम लोगों को राहत देगी। लेकिन, सत्ता में आने के बाद कैप्टन सरकार ने यह कदम नहीं उठाया और कहा कि निजी थर्मल प्लांटों के साथ समझौतों को रद नहीं किया जा सकता। राज्य में अभी कृषि, दलितों, पिछड़ों और उद्योगों को निशुल्क बिजली या बिजली में सब्सिडी देकर राहत दी जा रही है, लेकिन घरेलू और कमर्शियल सेक्टर पर इसका बोझ बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी महंगी बिजली को मुद्दा बनाया हुआ है।

पंजाब कांग्रेस की कलह को शांत करने के लिए बनाई गई कमेटी के सामने भी विधायकों ने महंगी बिजली का मुद्दा उठाया। इसके अलावा उठाए गए अन्य मुद्दों के आधार पर जिन 18 मुद्दों की सूची भेजी गई है उनमें सभी परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का भी मामला है। यही नहीं, बेअदबी कांड, रेत माफिया पर लगाम, ट्रांसपोर्ट माफिया पर लगाम के साथ-साथ निजी थर्मल प्लाटों के साथ-साथ किए गए बिजली खरीद समझौतों को रद करने जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। बुधवार को कांग्रेस द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी ने कैप्टन को ये प्वाइंट दे दिए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री वापस दिल्ली से चंडीगढ़ आ गए है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी व कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे हरीश रावत ने इस बात की पुष्टि की है। रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री को 18 प्वाइंटों को तय समय-सीमा के भीतर पूरा करना होगा और इसकी बाकायदा आम लोगों को जानकारी भी देनी होगी। माना जा रहा है कि पिछले 23 दिनों से कांग्रेस का अंतर्कलह को खत्म करने के लिए पार्टी हाईकमान ने यह फार्मूला निकाला है।

भाजपा ने श्रावस्ती में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी किया घोषित, पूर्व सांसद दद्दन मिश्र को बनाया उम्मीदवार

श्रावस्ती। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। पूर्व सांसद दद्दन मिश्र को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष संजय कैराती ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रदेश नेतृत्व के निर्णय से अवगत कराया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की घोषणा होने के बाद से हर किसी की नजर भाजपा के टिकट पर लगी थी। सपा ने वार्ड नंबर 22 से जिला पंचायत सदस्य अनुराधा यादव को पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया था।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य पद पर 22 वार्डों में भाजपा समर्थित सिर्फ चार उम्मीदवार जीत दर्ज कर सके थे। वार्ड नंबर 17 से पूर्व सांसद दद्दन मिश्र विजयी हुए थे। चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही वे अध्यक्ष पद के लिए तैयारी में जुट गए थे। टिकट मांगने वाले जिला पंचायत सदस्यों में पूर्व सांसद को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था। गुरुवार से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री होनी है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा था कि बुधवार देर रात तक भाजपा की ओर से टिकट की घोषणा की जा सकती है। रात में 11.52 बजे भाजपा जिला अध्यक्ष संजय कैराती पटेल की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रदेश नेतृत्व के निर्णय से अवगत कराया गया है। इसमें पूर्व सांसद दद्दन मिश्र को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है। तीन लोग थे टिकट के दावेदार – भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए टिकट मांगने वालों में पूर्व सांसद दद्दन मिश्र के अलावा पूर्व महामंत्री रणवीर सिंह की पुत्रवधू अंशू सिंह व राजकीय ठेकेदार टीपी सिंह के पुत्र देव प्रताप सिंह का नाम शामिल था। जिला कार्यकारिणी की ओर से तीनों लोगों के नाम का प्रस्ताव भेजा गया था। प्रदेश नेतृत्व ने पूर्व सांसद के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी है।

राजनीति में और बड़ा हुआ कद – बसपा के टिकट पर विधायक व राज्य मंत्री रहे दद्दन मिश्र दूसरी पारी में भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसके बाद वर्ष 2014 के लोकसभा चुना में भाजपा के टिकट पर अतीक अहमद को हरा कर वे सांसद चुने गए। इस चुनाव के बाद उनका राजनैतिक कद काफी बढ़ गया। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सांसद के तौर पर दूसरी पारी के लिए उन्होंने ताकत झोंकी, लेकिन महागठबंधन से बसपा के उम्मीदवार रामशिरोमणि वर्मा से मामूली वोटों से उन्हें शिकस्त खानी पड़ी। चुनाव हारने के बाद भी वे क्षेत्र में सक्रिय रहे। इसका परिणाम जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में मिला। कड़े मुकाबले में उन्होंने जीत दर्ज जी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए टिकट मिलने के बाद जिले की राजनीति में उनका कद और बढ़ गया है।

भाजपा ने सहयोगी को दी सीट, जौनपुर व सोनभद्र में अपना दल लड़एगा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी

लखनऊ । भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन का धर्म निभाते हुए अपने सहयोग अपना दल (एस) को जिला पंचायत अध्यक्ष के 75 पदों में से दो सीट पर प्रत्याशी उतारने पर मुहर लगा दी है। अपना दल (एस) की नेता अनुप्रिया पटेल ने बीते दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर भेंट की थी, इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात हुई थी।

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बेहद गंभीर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सहयोगी रहे अपने सभी दलों को साथ लेने की मुहिम में है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल (एस) जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी अपने साथ ही रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल (सोनेलाल) को दो सीट दी है, जहां से यह अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। अपना दल को जौनपुर तथा सोनभद्र की सीट दी गई है। अब पार्टी इन दोनों जिलों में अपना प्रत्याशी तय करके उसके नाम की घोषणा करेगी। भाजपा ने एनडीए में अपने घटक अपना दल (एस) को जौनपुर और सोनभद्र जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट दी है। पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी थीं और वह मिर्जापुर से लगातार दूसरी बार सांसद हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार में अपना दल के नेता जय प्रताप सिंह जैकी मंत्री भी हैं।

प्रयागराज में मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज टीकाकरण केंद्र में कोविड-19 वैक्सीन की खुराक लेते हुए एक युवती ने सेल्फी ली।

मौलाना उमर गौतम पर कसा एटीएस का शिकंजा, लखनऊ में अल हसन इंस्टीट्यूट पर छापा व जांच

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मतांतरण करने के दो आरोपितो में से एक मौलाना मोहम्मद उमर गौतम की रिमांड मिलने से बाद अब उत्तर प्रदेश एटीएस ने उसके ऊपर तगड़ा शिकंजा कस दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के भी इस प्रकरण की लगातार मॉनिणरिंग करने के कारण ही जांच एजेंसियां भर लगातार बड़े अभियान में लगी हैं।

मौलाना उमर गौतम ने लखनऊ में अपना बड़ा नेटवर्क बना लिया था। एक शिक्षण संस्थान में तो वह वाइस चेयरमैन था जबकि मैंगों बेल्ट में उसकी अल हसन इंस्टीट्यूट में गरीब लोगों को मतांतरण के लिए प्रेरित करने का काम चलता था। उत्तर प्रदेश एटीएस ने गुरुवार को अल हसन इंस्टीट्यूट, मलिहाबाद में छापा मारा है। काकोरी क्षेत्र के रहमान खेड़ा में अल हसन इंस्टीट्यूट, मलिहाबाद में एटीएस की टीम के सदस्य यहां पर मतांतरण तथा अन्य मामलों की जांच में लगे हैं। अब माना जा रहा है कि यहां पर एजेंसी को टेरर एंगल भी मिला है। एटीएस ने मौलाना मोहम्मद उमर गौतम के साथ उसके साथी जहांगीर की हर हरकत पर बारीक नजर रखी है। मतांतरण का बड़ा मामला सामने आने के बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर पहलू की सख्त जांच कर अन्य सभी सभी दोषियों को गिरफ्तार करने का निर्देश भी दिया है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने बीते सोमवार को लखनऊ से मोहम्मद उमर गौतम पुत्र स्वर्गीय धनराज सिंह गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी को हजार से अधिक लोगों के मतांतरण के मामले में गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश एटीएस को मंगलवार को इनकी सात दिन की रिमांड मिली है। अब जांच एजेंसी इनके बड़े राज उगलवाने के प्रयास में लगी है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम(एनएसए) के तहत कार्रवाई करने के साथ ही इनकी संपत्ति भी जब्त करने का निर्देश दे दिया है।

प्रेसिडेंशियल ट्रेन से पहले 130 की स्पीड से दौड़ी ट्रायल ट्रेन, रूरा में कुछ देर रुकी

कानपुर । राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के कानपुर आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर है। इसी क्रम में प्रेसिडेंशियल ट्रेन का रूट परीक्षण गुरुवार की सुबह किया गया। नई दिल्ली से चली ट्रेन सुबह वाया टूंडला-इटावा-फफूंद-कंचौसी, झींझक होते हुए कानपुर की ओर बढ़ रही है। 130 किमी की रफ्तार से चल रही यह ट्रेन रूरा स्टशन पर भी कुछ देर के लिए रुकी। इसके बाद फिर कानपुर के लिए आगे बढ़ गई। इस दौरान सभी रेलवे स्टेशन, हाल्ट स्टेशन और क्रासिंग पर रेलवे अधिकारी, आरपीएफ, जीआरपी और पुलिस के अधिकारी मुस्तैद दिखाई दिए।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द 25 जून की शाम प्रेसिडेंशियल ट्रेन से कानपुर आ रहे हैं, यहां से वह अपने पैतृक गांव परौंख झींझक कानपुर देहात जाएंगे। उनके आगमन को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और झींझक स्टेशन पर भी सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त कर लिए गए हैं। आसपास जिलों के स्टेशन पर भी अलर्ट कर दिया गया है। राष्ट्रपति स्पेशल सैलून दिल्ली वाया टूंडला-इटावा-फफूंद-कंचौसी, झींझक होते हुए कानपुर पहुंचेगी।

एक दिन पहले गुरुवार को स्पेशल सैलून के रूट का परीक्षण नई दिल्ली-लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस से किया गया। यह ट्रेन 130 किमी की गति से गुजरी। रूट पर पड़ने वाले रेलवे स्टेशन अछल्दा, न्यू अछल्दा, कंचौसी, न्यू कंचौसी, फफूंद व पाता समेत सभी क्रासिंग और स्टेशनों पर पुलिस व रेलवे प्रशासन का पहरा रहेगा। यह ट्रेन कंचौसी रेलवे स्टेशन पर सुबह करीब 10.25 बजे पहुंची।

ट्रेन का ठहराव औरैया सीमा के किसी स्टेशन पर नहीं था, कुछ देर के लिए ट्रेन रूरा स्टेशन पर रुकी और फिर कानपुर के लिए रवाना हो गई। अछल्दा रेलवे स्टेशन पर एसडीएम राशिद अली के साथ नायब तहसीलदार अभिनव वर्मा पहुंचे थे। स्टेशनों पर छोटी-बड़ी सारी कमियों को दूर करने में उत्तर मध्य रेलवे की टीम लगी है।

जींस-टीशर्ट वाली भिखारिनों ने होटल को बनाया था ठिकाना, कार वालों से मांगती थी दो सौ रुपये भीख

कानपुर । ब्रांडेड जींस और टीशर्ट पहनकर भीख मांगने वाली महिलाओं ने एक होटल को अपना ठिकाना बना रखा था। हाईफाई ये भिखारिनें कार वालों को रोककर कम से कम दो सौ रुपये की भीख मांगती थी। पहले बर्रा में 27 युवतियां पकड़ी गई थीं तो अब काकादेव से दस महिलाएं पकड़ी गई हैं। गोद में बच्चा लेकर भीख मांगने वाली ये महिलाएं कार वालों को ही निशाना बनाती हैं।

कानपुर सक्रिय है भिखारिनों का गिरोह

जींस टाप पहनकर भीख मांगने वाली महिलाओं का गिरोह कानपुर सक्रिय है और हरबंश मोहाल के एक होटल को अपना अड्डा बना रखा था। अब काकादेव में इस तरह की महिलाओं के पकड़े जाने के बाद पुलिस आयुक्त ने गहरी नाराजगी जताई है। कादेव थाना पुलिस को मंगलवार को सूचना मिली थी कि देवकी टाकीज चौराहे के पास आठ से 10 महिलाएं गोदी में बच्चा लेकर भीख मांग रही हैं। सूचना पर पहुंची काकादेव पुलिस ने आठ महिलाओं को गिरफ्तार कर भिक्षावृत्ति अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी। जबरन भीख मांगने को लेकर पिछले दिनों बर्रा में भी विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने एक होटल में छापा मारकर वहां से भीख मांगने वाली 27 महिलाओं व युवतियों को पकड़ा था। हालांकि पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।

इस तरह बनाती हैं शिकार- कानपुर शहर में पॉश इलाके इन महिलाओं का ठिकाना होते हैं, जहां कार सवार लोगों का ज्यादा आवागमन होता है। पहले से तैयारी के साथ गोद में बच्चा लेकर अपार्टमेंट और घरों के बाहर निश्चित समय पर पहुंच जाती हैं। इसके बाद अपार्टमेंट या कोठियों से कार बाहर निकलते ही रोक लेती हैं और खुद को अच्छे का घर का बताकर आर्थिक तंगी का हवाला देती हैं। बच्चों को कई दिन से भूखा बताकर दो तीन सौ रुपये की मांग करती हैं। जींस-टीशर्ट में महिला को ठीक ठाक मानकर उसकी बातों पर लोग विश्वास करके भीख दे देते हैं। मुख्य चौराहों पर भी ये महिला भिखारिनें अक्सर गोद में बच्चों को लिये दिखाई दे जाती हैं।

होटलों में ठहरी थी महिलाएं- अच्छे घरों की दिखाई देने वाली यह महिलाएं कोरोना काल में आर्थिक समस्या का हवाला देकर कार व अन्य वाहन चालकों से मदद के नाम पर भीख मांगती हैं। खास बात यह है कि जांच के बाद सामने आया कि यह महिलाएं राजस्थान और गुजरात की रहने वाली हैं और यहां हरबंश मोहाल स्थित एक होटल में रहती थीं और जींस पहनकर शहर में भीख मांगती हैं, क्योंकि घाघरा पहनने से लोग उन्हें बच्चा चोर समझ रहे थे। यही नहीं पिछले दिनों कोहना में ठगी के आरोप में जो तीन सिख पकड़े गए थे, वह भी यहीं के होटलों में ठहरे थे। लगातार तीसरी घटना के बाद पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि होटलों में चेकिंग के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है।

तेजस्वी यादव के पटना लौटते ही जोश में राजद कार्यकर्ता, लगाए पोस्टर

पटना । बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना लौटते की कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक पर निशाना साधा जाने लगा है। इस क्रम में महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर राजद ने सीधा हमला बोला है। राजद कार्यालय के सामने लगाए गए पोस्टर पर विभिन्न सामग्री की कीमतों को दर्शाया गया है।

सैंया हमार कमाय जात है- पोस्टर के ऊपर में लिखा है सैंया हमार कमाय जात है, महंगाई डाइन खाए जात है। इसके बाद सरसों तेल की कीमत 220 रुपये, रिफाइन 180 रुपये, अरहर दाल 120 रुपये समेत विभिन्न सामग्री की कीमतें दर्शायी गई हैं। पेट्रोल की कीमत 106 एवं डीजल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर लिखी गई है। तस्वीर के बीच में बड़े अक्षर में महंगाई लिखा है। आगे लिखा है कि जब विपक्ष में होते हैं तो महगाई पर बड़ा सवाल उठाते हैं। जब सत्ता में आते हैं तो उसका जिम्मेदार विपक्ष को बताते हैं।

महंगाई से त्रस्त है जनता, कैसे तले पकौड़ा भी -पोस्टर लगाने वाले राजद के नेता जेमर कुमार यादव ने कहा कि केंद्र सरकार विकास की बात करती है। लेकिन कहां विकास है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया है। देश के 35 फीसद लोग प्रतिदिन भूखे पेट सोते हैं। ऐसे में विकास का मतलब क्या है। यह तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तलो लेकिन आज तो युवा वह भी नहीं कर सकता क्योंकि तेल की कीमत दो सौ के पार हो गई है। बता दें कि राज्य में पोस्टर वार कोई नया नहीं है। विभिन्न मौके पर राजद, जदयू की ओर से पोस्टर लगाकर एक-दूसरे पर हमला किया जाता है। अब देखना है कि राजद के इस पोस्टर के जवाब में सत्ताधारी दल की ओर से क्या किया जाता है।

बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी, हर गांव पर है नज़र

प्रयागराज । बहुजन समाज पार्टी इन दिनों विधानसभा चुनाव 2022 की जमीन तैयार करने में जुटी है। प्रयागराज में बसपा जिलाध्यक्ष से लेकर, सेक्टर प्रभारी, मुख्य सेक्टर प्रभारी एयर भाईचारा कमेटी के प्रभारी लोगों का मन टटोल रहे हैं। सियासत की अगली पारी खेलने के लिए पार्टी जन गंगापार और यमुनापार में ग्रामीणों के पास पहुंच रहे हैं।

इसी के तहत बारा विधानसभा क्षेत्र के गौहनिया में भाईचारा कमेटी की बैठक हुई। भाईचारा कमेटी की बैठक में मुख्य अतिथि इलाहाबाद, मीरजापुर, फैजाबाद व वाराणसी मंडल के मुख्य सेक्टर संयोजक भाईचारा विश्वनाथ पाल रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने सीख दी। कहा कि कार्यकर्ता अभी से ही विधानसभा-2022 के चुनाव में लग जाएं। साथ ही जमीनी स्तर से लेकर बूथ स्तर तक गांव-गांव जाकर बसपा की नीतियों को बताएं। कानून व्यवस्था व महामाया आवास, पेंशन, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं गरीब लोगों को मिल सके। उक्त कार्यक्रम में विधान सभा संयोजक भाईचारा शिवशंकर पाल व हरिश्चंद्र कुरील को अहम जिम्मेदारी दी गई।

इनकी रही उपस्थिति- पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज भाईचारा की बैठक में सेक्टर प्रभारी इलाहाबाद, मीरजापुर मंडल सर्वेंद्र गौतम व अशोक कुमार बिंद, पप्पू भारती मुख्य सेक्टर प्रभारी इलाहाबाद मंडल व जगदंबा प्रसाद कुशवाहा, समरजीत चौधरी जिला सचिव बारा, अशोक पाल,यशवंत आदि समस्त विधानसभा बारा के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

अब सियासी अखाड़े में चिराग का दिखेगा नया अंदाजः तेजस्वी का ऑफर ठुकराया, बिहार में अकेले लड़ेंगे चुनाव

पटना । लोक जनशक्ति पार्टी में टूट और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं मिलने से चिराग पासवान अब राजनीतिक अखाड़े में नए अंदाज में दिखेंगे। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने चिराग को भाई बताते हुए महागठबंधन में शामिल होने का आफर दिया है, लेकिन चिराग ने इसपर चुप्पी साध ली है। चिराग के करीबी और एलजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अशरफ अंसारी के मुताबिक चिराग पासवान का स्पष्ट का मानना है कि अब किसी गठबंधन में जाने से बेहतर है कि राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव की अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए।

तेजस्वी के आफर को नहीं देंगे तवज्जो, करेंगे आशीर्वाद यात्रा- अशरफ अंसारी ने दिल्ली से दूरभाष पर बताया कि चिराग पासवान फिलहाल तेजस्वी यादव के किसी ऑफर को तवज्जो नहीं देंगे। वे अभी आशीर्वाद यात्रा के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। पांच जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती पर हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से आशीर्वाद यात्रा निकाली जानी है। यह यात्रा उनके राजनीतिक जीवन के लिए फिलहाल बेहद जरूरी हो गई है।

बीजेपी की चुप्पी परेशान, पीएम मोदी से मध्यस्थता की उम्मीद- यहां बता दें कि एलजेपी में टूट होने पर बीजेपी का साथ नहीं मिलने पर चिराग ने कहा है कि खामोशी से हनुमान का वध राम को देखना शोभा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने हमेशा से बीजेपी का साथ दिया है, लेकिन आज जब हम मुश्किल में है तो बीजेपी के नेताओं ने चुप्पी साध ली है। चिराग पासवान ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मध्यस्थता की उम्मीद है। विश्वास है कि प्रधानमंत्री जल्द ही इस मामले (एलजेपी की टूट) में हस्तक्षेप कर सब कुछ सही करेंगे।

एलजेपी दो-फाड़, दोनों गुटों ने किया है पार्टी पर दावा- विदित हो कि एलजेपी के छह में से पांच सासंदों ने चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में चिराग को संसदीय दल के नेता तथा पार्टी अध्यक्ष के पदों से हटाने की घोषणा की है। उधर, चिराग पासवान ने भी उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। एलजेपी के दोनों गुट पार्टी पर दावा कर रहे है।

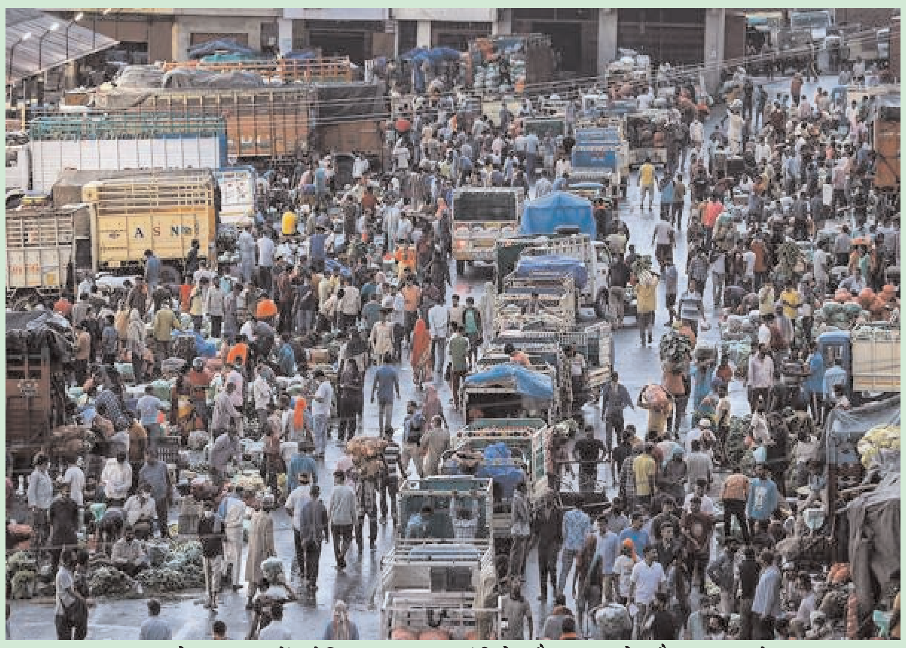

जम्मू के नरवाल में कोविड -19 तालाबंदी के दौरान छूट के दौरान एक थोक सब्जी बाजार में लोगों की भीड़ ।

शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में गुप्कर एलायंस की सदस्य महबूबा मुफ्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए।

अगरतला के जगन्नाथ मंदिर में देबा स्नान पूर्णिमा के अवसर पर पुजारी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों पर दूध डालते हुए।

एक नजर

कोच्चि और कारवार के दो दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन परियोजना की करेंगे समीक्षा

कोच्चि । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज केरल के कोच्चि और कर्नाटक के कारवार के दौरे पर है। रक्षा मंत्री कारवार और कोच्चि के दो दिवसीय दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। रक्षा मंत्री नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के साथ एक विशेष विमान द्वारा कोच्चि के नौसेना वायु स्टेशन आईएनएस गरुड़ में शाम 7.30 बजे पहुंचेंगे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री शुक्रवार को सुबह 9.45 बजे कोचीन पोर्ट ट्रस्ट घाट पर स्वदेशी विमान वाहक का दौरा करेंगे और परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

नौसेना की परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा- इस दौरान राजनाथ सिंह दक्षिणी नौसेना कमान की विभिन्न प्रशिक्षण इकाइयों का दौरा करेंगे और नौसेना की परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। अपनी दो दिवसीय यात्रा के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री शुक्रवार दोपहर तीन बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 जून को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) पहुंचकर देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत के निर्माण की समीक्षा करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राजनाथ आज शाम को को कोच्चि पहुंचेंगे और शुक्रवार को सीएसएल में पोत के निर्माण कार्य को देखेंगे। बता दें कि रक्षा मंत्री का यह दो दिवसीय दौरा विमानवाहक पोत के समुद्री ट्रायल में देरी होने के दौरान किया जा रहा है। गौरतलब है कि पोत को इस साल के पहले छह महीनों में समुद्र में उतारकर उसका परीक्षण किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण इस परीक्षण को टाल दिया गया था।

पुलिस से मुठभेड़ के बाद लग्जरी कार छोड़ भागे तस्कर, कार से दो करोड़ रुपए, 78 किलो अफीम व पिस्टन की मैग्जीन कारतूस भी मिले

उदयपुर । चित्तौड़गढ़ जिले के देवरी गांव में नाकाबंदी के दौरान पुलिस की तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से हुई फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ किन्तु तस्कर लग्जरी कार छोड़कर भाग निकले। उनकी कार से 78 किलो अफीम के अलावा पिस्टन की मैग्जीन तथा कारतूस बरामद हुए। बरामद अफीम की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में दो करोड़ रुपए से अधिक बताई। बरामद कार में दो नंबर प्लेट भी मिलीं, जिनमें से एक महाराष्ट्र की जबकि दूसरी जयपुर की थी। मिली जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ थाना पुलिस देवरी गांव के समीप उदयपुर हाई वे पर होटल कमल के पास नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान चित्तौड़गढ़ की ओर से आई फारचूनर कार को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। किन्तु उसमें सवार तस्कर ने कार की रफ्तार तेज कर दी। सदर थाने के हैड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह की चतुराई की वजह से तस्करों की कार पकड़ी गई। पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भागते समय हैड कांस्टेबल भूपेंद्र ने स्टॉप स्टिक तेजी से फैंकी और उसके उपर से गुजर रही तस्करों की कार का टायर पंक्चर हो गया। हालांकि इसके बावजूद तस्करों ने कार नहीं रोकी, बल्कि पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में पुलिस ने भी फायर किए। पंक्चर होने के बावजूद तस्करों ने कार नहीं रोकी बल्कि उसे दौड़ाते रहे। रिठौला चौराहे के आगे तस्करों ने अपनी कार एक सर्विस रोड पर ले ली जो आगे बंद थी। जहां तस्कर कार को छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने बताया कि तस्करों की संख्या दो थी। पुलिस ने जब तस्करों की कार की तलाशी ली तो उसमें तीन कट्टों में बड़ी मात्रा में अफीम बरामद की। जो तुलाने पर 78 किलो पाई गई। कार में दो नंबर प्लेट, जिनमें से एक महाराष्ट्र की और दूसरी जयपुर की थी। पिस्टल की एक मैग्जीन तथा पांच जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस अब कार पर लगी नंबर प्लेट के आधार पर उसके मालिक का पता लगाने की कोशिश कर रही है। तस्करों के नाकाबंदी कर रही पुलिस पर फायरिंग की सूचना पर जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह देवल, सदर थानाधिकारी दर्शन सिंह मौके पर पहुंचे। बुलाए गए अतिरिक्त पुलिस जाब्ते ने खेतों तथा पहाड़ियों पर सर्च ऑपरेशन किया, ताकि तस्कर बरामद हो सकें लेकिन तीन घंटे तक चलाए अभियान के बावजूद उनका पता नहीं चल पाया। तस्करों की धरपकड़ के लिए चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में नाकाबंदी कराई गई।

कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबले के लिए तैयार मुंबई, बीएमसी ने किए खास इंतजाम

मुंबई । बृहन्मुंबई नगर निगम ने बुधवार को कहा कि वह महानगर में कोरोना वायरस संक्रमण की संभावित तीसरी लहर का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है और उसने मामलों में वृद्धि से निपटने के लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का भी इंतजाम कर लिया है। अतिरिक्त नगर आयुक्त सुरेश काकानी ने दो दिवसीय समीक्षा के बाद एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि बीएमसी ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए विभिन्न अस्पतालों, जंबो कोविड केंद्रों और कोविड देखभाल केंद्रों में रोगियों के इलाज के लिए बेड तैयार कर लिए हैं। विज्ञप्ति के अनुसार मुंबई में सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ जंबो केंद्रों में बच्चों के लिए अलग वार्ड स्थापित किए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी अलग वार्ड बनाए गए हैं। नगरिक निकाय ने कहा कि भले ही बीएमसी प्रशासन तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयार है लेकिन इसके बावजूद नागरिकों को कोविड-19 की रोकथाम से संबंधित सभी निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। विभिन्न नागरिक अस्पताल, जंबो कोविड केंद्र, कोरोना केयर सेंटर-1 और कोरोना केयर सेंटर -2 कोविड -19 रोगियों के लिए बेड से लैस हैं, बीएमसी ने बताया यहां लगभग 2,000 वेंटिलेटर मौजूद हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पहले चरण में, नागरिक निकाय ने जंबो कोविड -19 केंद्रों में 7,307 बेड स्थापित किए थे और वहां लगभग 77 मरीजों का इलाज किया गया था, जबकि दूसरे चरण में युद्ध स्तर पर 8,350 नए बेड स्थापित किए जा रहे हैं। बीएमसी के अनुसार, 8,350 नए बेड में से कांजुरमार्ग और मलाड में 2,200, नेस्को गोरेगांव में 1,500, सायन में 1,200, भायखला में 700, महालक्ष्मी रेसकोर्स में 450 और एनएससीआई वर्ली में 100 बेड स्थापित किए गए हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है, जंबो कोविड -19 केंद्रों की कुल बिस्तर क्षमता को बढ़ाकर 15,657 कर दिया गया है। इनमें से 70 प्रतिशत बिस्तरों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की सुविधा है और प्रत्येक जंबो कोविड -19 केंद्र में तरल चिकित्सा भंडारण टैंक है। बीएमसी ने कहा कि विभिन्न अस्पतालों में वायुमंडलीय हवा से मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए सिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर बैक-अप भी होगा। इससे गंभीर कोरोनावायरस रोगियों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी।

कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार, फिर भी मास्क पहनने को लेकर गंभीर नहीं लोग

नई दिल्ली । डाक्टरों ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और शारीरिक दूरी अपनाने की सलाह दी है। लेकिन देश के कई हिस्सों में या तो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या फिर दिखावे के लिए ठोढ़ी पर लटका रखते हैं। यह हालत तब है जब अत्यधिक संक्रामक डेल्टा प्लस वैरिएंट ने कई शहरों में दस्तक दे दी है और विज्ञानियों ने तीसरी लहर के छह से आठ सप्ताह में आने की चेतावनी जारी की है। लोगों के मास्क पहनने की प्रवृत्ति को लेकर लोकल सर्किल ने एक सर्वे किया। इस दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि टीकाकरण केंद्रों सहित शहरों और जिलों में लोग मास्क पहनने का कितना पालन कर रहे हैं। इस दौरान 312 जिलों के 33,000 से अधिक नागरिकों से उनकी प्रतिक्रियाएं ली गईं।

मास्क पहनने से 30 फीसद कम हो जाता है संक्रमण का जोखिम- स्वास्थ्य मंत्रलय द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि दो व्यक्तियों के मास्क नहीं पहनने और पर्याप्त शारीरिक दूरी नहीं रखने से संक्रमण का खतरा 90 फीसद होता है। हालांकि अगर गैर संक्रामक व्यक्ति मास्क पहनता है तो संक्रमण का जोखिम 30 फीसद तक कम हो जाता है। गाइडलाइन में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि ड्रापलेट्स और एरोसोल से संक्रमित होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यह हवा में 10 मीटर दूर तक जा सकती हैं। अगर इन प्रोटोकाल का पालन नहीं किया जाता है कि कोरोना संक्रमण के कुछ थोड़े लोगों से बहुत बड़ी आबादी में फैलने का खतरा रहता है।

सुपरस्प्रेडर का जरिया बन रहे टीकाकरण केंद्र- देश में टीकाकरण अभियान जोरों पर है।

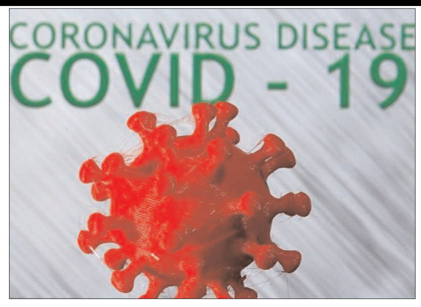

कई केंद्रों पर भीड़ के साथ अराजकता का भी माहौल देखने को मिल रहा है। केरल में तो टीकाकरण केंद्रों पर उमड़ रही भीड़ का हाई कोर्ट को स्वत- संज्ञान लेना पड़ा। जिसके बाद प्रदेश सरकार ने आन स्पाट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बंद कर दी। लोकल सर्किल से बात करते हुए अधिकांश लोगों ने कहा कि टीकाकरण के बाद वह कोरोना से संक्रमित हो गए। विशेषज्ञों के मुताबिक मास्क प्रोटोकाल का पालन नहीं किए जाने के चलते टीकाकरण केंद्र सुपरस्प्रेडर का जरिया बन रहे हैं।

67 फीसद बोले, बहुत सीमित संख्या में पहनते हैं मास्क- जब लोगों से उनके क्षेत्र में मास्क प्रोटोकाल के बारे में पूछा गया तो मात्र दो फीसद ने कहा कि इसका पालन नहीं किया जा रहा है। जबकि 10 फीसद लोगों का कहना था कि 0-30 फीसद लोग मास्क पहन रहे हैं। वहीं 55 फीसद ने 30-60 फीसद, 23 फीसद ने 60-90 फीसद और नौ फीसद लोगों ने कहा कि 90 फीसद से ज्यादा लोग मास्क पहनते हैं। औसत निकाला जाए तो 67 फीसद लोगों का मानना है कि उनके क्षेत्र में सीमित संख्या में मास्क पहनने के नियम का पालन हो रहा है।

टीकाकरण केंद्रों पर सीमित संख्या में मास्क पहनते हैं लोग- जब लोकल सर्किल ने पूछा कि टीकाकरण केंद्रों पर मास्क पहनने के प्रोटोकाल का कितने लोग पालन करते हैं तो मात्र दो फीसद ने कहा कि इसका बिल्कुल अनुपालन नहीं किया जाता है। चार फीसद ने कहा कि 0-30 फीसद मास्क पहनते हैं, 26 फीसद ने कहा 30-60 फीसद, 47 फीसद ने कहा कि 60-90 फीसद और 21 फीसद ने कहा कि 90 फीसद से अधिक लोग ठीक तरह से मास्क पहनते हैं। अगर इसका औसत निकाला जाए तो 32 फीसद लोगों का मानना है कि टीकाकरण केंद्रों पर मास्क पहनने के प्रोटोकाल का सीमित संख्या में अनुपालन किया जाता है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मिली 30 करोड़ से अधिक कोरोना डोज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए ताजा आंकडे

नई दिल्ली । केंद्र द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 30 करोड़ (30,33,27,440) से अधिक वैक्सीन खुराक प्रदान की जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह आठ बजे तक उपल्बध किए गए आंकड़ों के अनुसार इनमें वेस्टेज 28,43,40,936 खुराक शामिल है। देश में कोरोना की ताजा स्थिति की बात करें तो फिलहाल संक्रमण के मामलों में कमी जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के कुल 54,069 केस सामने आए हैं। इस दौरान 1321 लोगों मौत हुई है।

इसके साथ ही देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। सक्रिय मामलों में भी गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 68,885 लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना से अब तक कुल 2 करोड़ 90 लाख 63 हजार 740 लोग ठीक हो चुके हैं। कुल आंकडे की बात करें तो देश में कोरोना का कुल आंकड़ा तीन करोड़ के पार पहुंच गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक कुल 3 करोड़ 82 हजार 778 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब तक कुल 3 लाख 91 हजार 981 लोगों की मौत हुई है।

क्या नए डेल्टा प्लस वैरिएंट को बेअसर कर सकती हैं भारतीय वैक्सीन शोध में जुटे देश के वैज्ञानिक

नई दिल्ली । भारत में कोरोना वायरस का एक नया रूप- डेल्टा प्लस वैरिएंट सामने आया है। देश के चार राज्यों- महाराष्ट्र केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में अब तक इसके कुल 40 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वैरिएंट के उभार ने एक बार फिर भारत से लेकर दुनियाभर की सरकारों और विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। देश के कुछ हिस्सों में डेल्टा प्लस वैरिएंट का पता चलने के बाद अब देश के वैज्ञानिक इसको बेअसर करने के हथियार खोजने में जुटे हुए हैं। देश के वैज्ञानिकों ने फैसला किया है कि वे इसको लेकर शोध करेंगे कि भारतीय वैक्सीन कोरोना वायरस के नए डेल्टा प्लस वैरिएंट के खिलाफ कितनी असरदार है और क्या ये डेल्टा प्लस वैरिएंट को बेअसर कर सकती है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने यह देखने के लिए एक अध्ययन करने का फैसला किया है कि क्या भारत में मौजूद वैक्सीन कोरोना के इस नए और खतरनाक वैरिएंट के खिलाफ कारगर हैं या नहीं। सरकार के मुताबिक, देश में डेल्टा प्लस के मामले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश (भोपाल और शिवपुरी) के साथ तमिलनाडु में भी पाए गए हैं।

दोनों भारतीय वैक्सीन पर हो रहा शोध- इस अध्ययन में भारत की दोनों कोरोना वैक्सीन- कोवैक्सिन और कोविशील्ड को शामिल किए जाने की संभावना है। NIV की मैक्सिमम कंटेनमेंट फैसिलिटी की प्रमुख डॉ प्रज्ञा यादव ने कहा कि नए उभरे डेल्टा प्लस वैरिएंट में संभावित रूप से बढ़ी हुई संक्रमण क्षमता, फेफड़ों की कोशिकाओं के लिए उच्च बाध्यकारी क्षमता और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपचार के लिए प्रतिरोध है। इसको देखते हुए डेल्टा प्लस वैरिएंट एक चिंता का विषय हो सकता है और इसकी निगरानी की जानी चाहिए और प्रभावितों की रोकथाम की जानी चाहिए। यह पूछे जाने पर कि क्या मौजूदा टीके डेल्टा प्लस वैरिएंट के खिलाफ लड़ सकते हैं उन्होंने कहा कि नमूने एकत्र किए गए हैं और एक अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट से संबंधित पहले के आंकड़ों के अनुसार, भारत में मौजूदा वैक्सीन इसको बेअसर कर रही थी। हालांकि डेल्टा प्लस वैरिएंट के मामले में इसका असर थोड़ा कम जरूर हुआ है लेकिन ये अभी भी सुरक्षा दे रही है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमने इस वैरिएंट को अलग कर दिया है और हम जल्द ही एक अध्ययन करने जा रहे हैं।

हम अध्ययन के साथ वापस आएंगे।

कोरोना संक्रमण ने ली शीर्ष नक्सली कमांडर हरिभूषण की जान, छत्तीसगढ़ पुलिस ने की पुष्टि

बस्तर । शीर्ष नक्सली कमांडर और तेलंगाना राज्य समिति के सचिव यापा नारायण उर्फ हरिभूषण की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हो गई। सोमवार रात बीजापुर-सुकमा सीमा क्षेत्र में हरिभूषण के मौत की पुष्टि छत्तीसगढ़ पुलिस ने की। बस्तर के इंस्पेक्टर जनरल पी सुंदरराज के अनुसार पिछले कुछ दिनों से बस्तर पुलिस को इस तरह की जानकारी मिल रही थी कि तेलंगाना स्टेट कमेटी सेक्रेटरी हरिभूषण समेत कुछ सीनियर नक्सल कैडर कोरोना संक्रमण के चपेट में है और इनकी हालत गंभीर है। कुछ विश्वस्त सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की कि 21 जून को हरिभूषण की मौत मिनागुरम-भट्टीगुडम-जाबागट्टा जंगलों में हो गई। यह इलाका बीजापुर सुकमा जिले की सीमा पर है।

हरिभूषण के लिए 40 लाख रुपये का इनाम था। सुंदरराज के अनुसार हरिभूषण इन दिनों बीजापुर-सुकमा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के मिनागुरम-भट्टीगुडम-जबगट्टा गांव के जंगलों में था जहां उसकी मौत हुई। इंस्पेक्टर जनरल ने यह भी बताया कि हरिभूषण छत्तीसगढ़ में 22 से अधिक मामलों में शामिल रहा है। उन्होंने बताया कि हरिभूषण को यापा नारायण, जगन और दुर्योधन के नाम भी जाना जाता था।

उनके अनुसार हरिभूषण तेलंगाना के महबूबनगर के मेदागुडम गांव का निवासी था एवं उसपर 40 लाख रुपये से अधिक का इनाम है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इससे पहले दिसंबर 2019 में दक्षिण बस्तर क्षेत्र में केंद्रीय समिति के सदस्य और डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सचिव रमन्ना का बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी जबकि पिछले कुछ सप्ताह के दौरान कमेटी के दो वरिष्ठ सदस्यों गंगा और शोभरोई की भी कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत्यु हुई है। सुंदरराज ने आगे बताया कि नक्सली नक्सली शिविरों में कोरोना संक्रमण के कारण स्थिति चिंताजनक है तथा पिछले कुछ महीनों में कोरोना वायरस के कारण 16 से अधिक वरिष्ठ और मध्यम स्तर के नक्सलियों की मौत हुई है। कई अन्य नक्सली संक्रमित हैं।

महत्वपूर्ण बिंदुओं में जानें- जम्मू कश्मीर पर बुलाई केंद्र की सर्वदलीय बैठक में क्या उठ सकते हैं मुद्दे

नई दिल्ली । कश्मीर को लेकर गुरुवार को राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। इसकी वजह कश्मीर के मुद्दे पर पीएम मोदी के नेतृत्व में होने वाली एक बैठक है। इस बैठक में राज्य के करीब दर्जन भर नेता शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अनुच्छेद 370 को लेकर भी अटकलें बढ़ गई हैं। हालांकि केंद्र की तरफ से इस बैठक को लेकर ज्यादा कुछ खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्य के ताजा हालातों पर जहां केंद्र अपनी स्थिति साफ करेगा वहीं राज्य के नेताओं के भी विचारों को जानने और समझने की कोशिश करेगा। इसमें राज्य के नेताओं समेत पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजित डोभाल, समेत अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। जानें इससे जुड़ी कुछ खास बातें-

दोपहर तीन बजे से होने वाली इस बैठक को लेकर माना ये भी जा रहा है कि इसमें वहां पर विधानसभा चुनावों को लेकर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। आपको बता दें कि वर्ष 2018 के बाद से ही राज्य में कोई चुनी सरकार नहीं है। यहां पर फिलहाल राष्ट्रपति शासन है। मौजूदा वर्ष में यहां पर सीडीसी के चुनाव हुए थे। यहां पर विधानसभा चुनाव को टालने की एक बड़ी वजह यहां पर किया जा रहा परिसीमन भी है।

आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किए जाने के बाद इसकी जरूरत को महसूस किया गया था। फिलहाल दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। बुधवार को ही परिसीमन ग्रुप की भी बैठक हुई थी। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के 20 डिप्टी कमिश्नर ने हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में बदलाव होने के बाद से यहां पर विधानसभा की सीट भी बढ़ी हैं। आने वाले चुनाव में यहां की करीब 90 सीटों पर चुनाव संपन्न हो सकेगा।

आज होने वाली बैठक में राज्य के आंतरिक मसलों पर भी वार्ता होगी। इसके अलावा कहीं न कहीं इस बैठक में अफगानिस्तान में अमेरिका की गैर मौजूदगी की सूरत में राज्य के बढ़ते खतरे पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।

इस बैठक में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर के नेताओं में से कई ऐसे भी हैं जो अनुच्छेद 370 की मांग उठाते रहे हैं। माना जा रहा है कि वो इस मुद्दे को इस बैठक में भी जरूर उठाएंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद से ही राज्य के नेता ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनकी बात केंद्र नहीं सुन रहा है। ऐसे में ये बैठक उनकी इस नाराजगी को पूरी तरह से खत्म करने में सहायक साबित होने वाली है। खास बात ये भी है कि इस बैठक का केंद्र ने खुद आह्वान किया है।

राजस्थान सरकार ने ट्रासजेंडर्स समुदाय को सुरक्षा व संरक्षण देने को सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करेगी

जयपुर । राजस्थान सरकार ट्रासजेंडर्स समुदाय को सुरक्षा एवं संरक्षण देने लिहाज से ट्रासजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करेगी। यह प्रकोष्ठ ट्रासजेंडर्स के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम, निगरानी और इसमें इससे जुड़े मामलों को समय पर पंजीकृत कर जांच व अभियोजन सुनिश्चित करने का काम करेगा। राज्य के 16 हजार 517 ट्रासजेंडर्स के लिए अलग से पहचान पत्र भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह निर्णय ट्रासजेंडर समुदाय के विरूद्ध अपराधों को नियंत्रित करने और उनके सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी पहल साबित होगा। इस प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपी जाएगी । इस प्रकोष्ठ में कुल 6 लोग शामिल होंगे। इनमें 5 सरकारी और एक ट्रासजेंडर प्रतिनिधि शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार पूर्व में ट्रासजेंडरों को सरकारी योजनाओं का लाभ तीसरे लिंग के नाम से देने का निर्णय कर चुकी है।

सरकार ने कुछ समय पूर्व तय किया था कि राज्य में महिला एवं पुरूष के अतिरिक्त एक और लिंग ट्रासजेंडर होगा । इनका अलग से प्रमाण-पत्र बनेगा। सरकार के निर्णय के बाद प्रमाण -पत्र बनने लगे हैं। सरकार ने ट्रासजेंडर्स की गणना के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। सरकार द्वारा ट्रासजेडर्स को को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने के लिहाज से कोचिंग संस्थान भी खोलने की योजना है।

राजस्थान में नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए अब एक ही टेस्ट देना होगा। इसके आधार पर राज्य सरकार के सभी विभागों में भर्ती कर दी जाएगी। इस टेस्ट का नाम कॉमन एलेजिबिलिटी टेस्ट रखा गया। इसके आधार पर 20 तरह की भर्तियां हो सकेगी। यह टेस्ट स्नात्तक और 12वीं पास युवाओं के लिए भर्तियों के रास्ते खोलेगा। आदेश में कहा गया है कि अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों के लिए इस टेस्ट को क्लीयर करना अनिवार्य होगा।

इस पात्रता परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ही नियुक्ति दी जाएगी। इस परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा । बोर्ड द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन की ऐसी व्यवस्था की जाएगी,जिससे न केवल समान पात्रता परीक्षा बल्कि इस परीक्षा के आधार पर किसी भी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बार-बार आवेदन नहीं करना पड़े। सामान्यतप्रतिवर्ष भर्ती परीक्षा आयोजित होगी । ऑब्जेक्टिव प्रश्नपत्र के आधार पर होने वाली इस परीक्षा में एक ही चरण होगा ।

इस सॉफ्टवेयर की मदद से होगी वेंटिलेटर की आवश्यकता वाले रोगियों की पहचान

नई दिल्ली । एक सॉफ्टवेयर अब उन रोगियों की पहचान कर सकता है जिन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत है। समय रहते मरीज को रेफर करने से आपात स्थिति से पहले आवश्यक व्यवस्था करने में मदद मिलेगी। कोविड सेविरिटी स्कोर (सीएसएस) सॉफ्टवेयर नामक सॉफ्टवेयर में एक एल्गोरिथ्म है जो कारोना मरीजों को मापदंडों के एक सेट से मापता है। यह प्रत्येक रोगी के लिए एक पूर्व-निर्धारित डायनेमिक एल्गोरिथ्म के सहारे कई बार स्कोर करता है और एक ग्राफिकल ट्रेंड में इसे मैप करने के लिए एक कोविड सेविरिटी स्कोर (सीएसएस) देता है। इस सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी का उपयोग कोलकाता और उपनगरों में तीन सामुदायिक कोविड देखभाल केंद्रों में किया जा रहा है, जिसमें कोलकाता के बैरकपुर में एक 100-बेड का सरकारी कोविड देखभाल केंद्र भी शामिल है।कोरोना महामारी के दौरान अचानक आईसीयू और अन्य आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करना अस्पतालों के लिए एक चुनौती रही है। ऐसी स्थितियों के बारे में समय पर जानकारी स्वास्थ्य संकट को बेहतर ढंग से प्रबंधन करने में मदद करेगी।

फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन हेल्थ, कोलकाता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के साइंस फॉर इक्विटी, एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट (सीड) के समर्थन और आईआईटी गुवाहाटी के साथ सहभागिता कर डॉ. केविन धालीवाल, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और डॉ. सायंतन बंदोपाध्याय, पूर्व में डब्ल्यूएचओ (दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय) के सहयोग से एक एल्गोरिथम विकसित किया है जो लक्षणों, संकेतों, महत्वपूर्ण मापदंडों, परीक्षण रिपोर्ट और कोविड संक्रमित रोगी के संक्रमण को मापता है और प्रत्येक को एक पूर्व-निर्धारित डायनेमिक एल्गोरिथ्म के सहारे स्कोर करता है।

इस प्रकार एक कोविड सेविरिटी स्कोर (सीएसएस) देता है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) मॉडल में प्रशिक्षित और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), भारत सरकार द्वारा प्रमाणित फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इन सभी मापदंडों को एक टैबलेट कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें सॉफ्टवेयर लोड होता है।

सीएसएस को नियमित रूप से रिमोट बैठे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा कई बार निगरानी की जाती है, जिससे प्रत्येक मरीज के लिए डॉक्टर के परामर्श का समय कम हो जाता है और डॉक्टरों को मरीज को देखने के लिए आने की आवश्यकता कम हो जाती है। यह एक आईसीयू और रेफरल में वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत वाले रोगियों की शीघ्र पहचान में मदद कर सकता है, उन लोगों के लिए अस्पताल रेफरल को कम कर सकता है जिन्हें गंभीर देखभाल सहायता की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार अस्पताल में अधिक बेड की उपलब्धता हो पाएगी। यह उन रोगियों को चिकित्सा निगरानी में सहायता प्रदान करने में भी मदद करेगा जो इलाज का खर्च नहीं उठा सकते हैं या घर की खराब स्थिति के कारण घर पर अलग-थलग (आइसोलेट) नहीं हो सकते हैं। यह सुविधा केवल बेड और ऑक्सीजन सपोर्ट वाले कोविड केयर सेंटर्स के लिए बहुत बड़ी सहायता हो सकती है। हालांकि, इनवेसिव वेंटिलेशन के लिए इसमें कोई सुविधा नहीं है।

ईडी ने यूनिटेक मामले में हेलीकाप्टर और 101 भूखंडों को किया जब्त

नई दिल्ली, एजेंसी । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में एक हेलीकाप्टर व मुंबई स्थित 101 भूखंडों को जब्त कर लिया। जब्त संपत्ति की कीमत करीब 81 करोड़ रुपये आंकी गई है। मामले में अब तक 431 करोड़रपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। ईडी ने बुधवार को एक बयान में बताया कि पीएमएलए के तहत शिवालिक समूह और उसकी सहयोगी कंपनियों की संपत्तियों को जब्त किए जाने के आदेश जारी किए गए थे।

किंग रोटोर्स एयर चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के हेलीकाप्टर व मुंबई के शांता क्रूज इलाके में स्थित भूखंडों की कीमत 81.10 करोड़ के करीब है। केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, जांच के दौरान पता चला कि यूनिटेक समूह ने करीब 574 करोड़ रुपये की राशि अवैध तरीके से शिवालिक समूह को स्थानांतरित की, जिससे उसने हेलीकाप्टर व भूखंडों को खरीदा था।

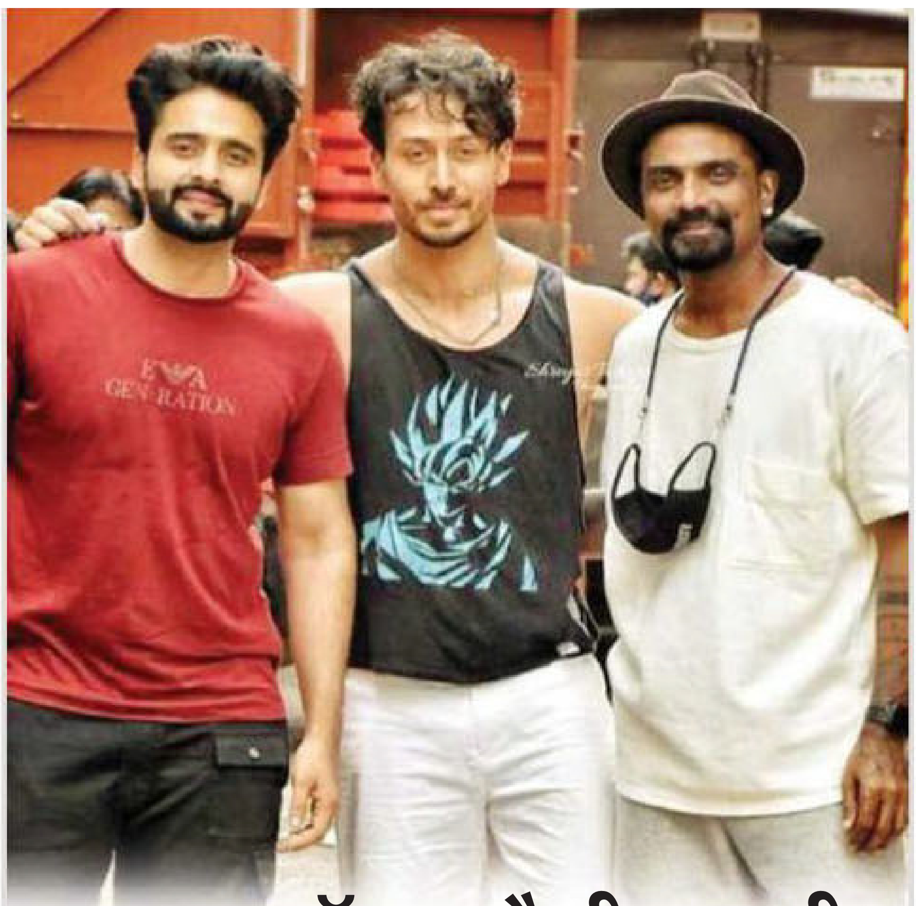

एक साथ स्पॉट हुए जैकी भगनानी, टाइगर श्रॉफ और रेमो डिसूजा, क्या नए प्रोजेक्ट की हो रही तैयारी?

फिल्म निर्माता जैकी भगनानी, एक्टर टाइगर श्रॉफ और कोरियोग्राफर-निर्देशक रेमो डिसूजा को हाल ही में मुंबई के एक स्टूडियो में देखा गया था और तब से टिनसेल टाउन में हलचल मच गई है। चर्चा है कि जैकी के लेबल जे जस्ट म्यूजिक के आने वाले गाने के लिए यह तिकड़ी एक साथ आ सकती है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट है?

इंडस्ट्री के सबसे युवा निर्माताओं में से एक, जैकी भगनानी हर बार एक नए प्रोजेक्ट के साथ आते हैं, ऐसे में घोषणा के साथ उत्साह पहले से ही बढ़ जाता है। निर्माता ने हाल ही में महाभारत की पौराणिक कहानी से प्रेरित एक फिल्म की भी घोषणा की थी जिसमें एक गुमनाम नायक कर्ण की कहानी है। युवा और डायनामिक निर्माता, जैकी भगनानी, पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले दीपशिखा देशमुख के साथ प्रोजेक्ट का निर्माण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

हालांकि अभी तक कास्टिंग की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फैंस इस प्रोजेक्ट के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं जो एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। निर्माता फिलहाल शूटिंग शेड्यूल, लोकेशन, बजट और स्टारकास्ट को फाइनल कर रहे हैं। जैकी की दूरदर्शी परियोजनाओं में से एक, टाइगर श्रॉफ और विकास बहल की आगामी फिल्म 'गणपथ' जिसे बॉक्सिंग और अंडरग्राउंड एमएमए पर आधारित फिल्म माना जा रहा है, उसकी शूटिंग जल्द ही शुरू होगी। बेल बॉटम भी वर्तमान में पोस्ट शूट प्रक्रिया में है, जिसे जैकी ने सभी सावधानियों का पालन करते हुए यूके में महामारी के बीच अपनी शूटिंग पूरी करने वाली पहली फिल्म के रूप में इसे चिह्नित किया है। अब, जो बात टाइगर-रेमो-जैकी को एक साथ लाती है, वह एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन हम टाइगर के किलर मूव्स, रेमो के स्टेप्स और जैकी के नेतृत्व में जे जस्ट म्यूजिक के नए ट्रैक का इंतजार कर रहे हैं।

सूर्यवंशी के लिए अक्षय ने फैन्स को कहा शुक्रिया बताया धूम 4 का सच

बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार का नाम उन सितारों में शुमार है, जो एक साल में करीब तीन फिल्में तो दर्शकों को दे ही देते हैं। कोविड के कारण अक्षय कुमार की कुछ फिल्में रिलीज नहीं हो पा रही हैं, वहीं कुछ फिल्में उनकी रिलीज होने जा रही हैं और इसके अलावा उनकी अन्य फिल्मों का भी शूट जारी है। इस बीच अक्षय कुमार ने धूम 4 को लेकर रिएक्शन दिया है।

धूम 4 में नहीं हैं अक्षय!

दरअसल हाल ही में अक्षय कुमार ने धूम 4 पर भी रिएक्शन दिया। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें थीं कि अक्षय कुमार ने आदित्य चोपड़ा से धूम 4 को लेकर मुलाकात की है। इस पर अक्षय ने कहा- 'मैं इस बारे में आपसे दो शब्द कहूंगा- फेक न्यूज।'

कब रिलीज होगी सूर्यवंशी?

इंटरव्यू में अक्षय कुमार से सूर्यवंशी की रिलीज पर भी सवाल पूछा गया, जिस पर अभिनेता ने कहा, 'करीब एक साल से सूर्यवंशी की रिलीज का हम सभी को इंतजार है। सबसे पहले तो मैं फैन्स को तहे दिल से शुक्रिया कहूंगा, जो अब भी फिल्म के लिए एक्साइटिड हैं। बाकी जैसा आप जानते हैं कि हम अप्रैल में फिल्म रिलीज करने जा रहे थे, जब हालात सुधर रहे थे, लेकिन प्लान फेल हो गया। जब भी कुछ प्लान के मुताबिक नहीं जाता है तब मेरी मां कहती हैं- फिकर न कर पुत्तर, इसमें भी कुछ अच्छा ही है। मैं कई सालों से इसपर विश्वास कर रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि तीसरी बार हम लकी हो जाएंगे'

अक्षय कुमार के प्रोजेक्टस

गौरतलब है कि हाल ही में बेल बॉटम की रिलीज डेट का एलान हुआ है, फिल्म 27 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी। इसके साथ ही एक ओर अक्षय जहां कुछ वक्त पहले तक फिल्म राम सेतु के शूट में बिजी थे तो दूसरी ओर वो फिल्म अतरंगी रे का शूट पूरा कर चुके हैं। अतरंगी रे में उनके साथ सारा अली खान और धनुष नजर आएंगे। इसके अलावा अक्षय की सूर्यवंशी भी रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन कोविड के चलते इसकी रिलीज फंसी है। इन सभी फिल्मों के साथ ही अक्षय कुमार के पास पृथ्वीराज, बच्चन पांडे और रक्षाबंधन भी है।

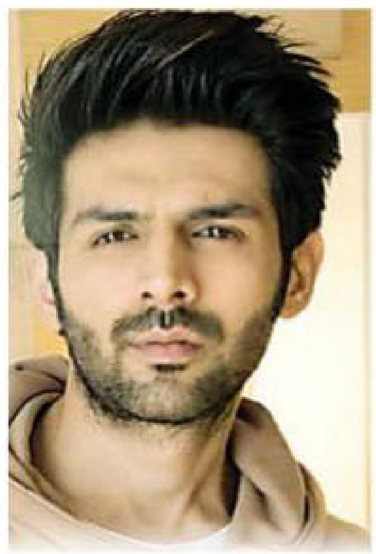

गेमिंग ऐप लॉन्च कर रहे हैं कार्तिक आर्यन

बॉलिवुड ऐक्टर कार्तिक आर्यन बीते दिनों बैक-टू-बैक दो फिल्मों से बाहर होने को लेकर चर्चा में बने हुए थे। हालांकि, उनकी पाइपलाइन में कई और फिल्में हैं। वहीं, कार्तिक आर्यन ने शनिवार के दिन एक वीडियो शेयर किया था। कार्तिक ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि किसी ने बदमाश को बुलाया.कल आ रहा है। कार्तिक का शनिवार के दिन इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर फैन्स काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि ऐक्टर जल्द ही अपनी नई फिल्म का खुलासा करने वाले हैं। अब कार्तिक ने वादे के मुताबिक वीडियो के राज से पर्दा हटा दिया है। कार्तिक ने वीडियो शेयर कर बताया कि यह वीडियो किसी फिल्म की शूटिंग का सीन नहीं बल्कि गेमिंग ऐप उन्थबद्य का लॉन्च वीडियो है। वीडियो शेयर करते हुए कार्तिक ने लिखा, 'अब मैं भी उन्थबद्य स्टार हूं।' वीडियो में कार्तिक आर्यन का एक्शन अवतार सबका ध्यान खींच रहा है। पहली बार ऐसा को मिला है कि कार्तिक गुंडों से फाइट करते और बंदूक चलाते दिखे रहे हैं। वीडियो में कार्तिक का एक्शन हीरो अवतार लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है।

कार्तिक आर्यन के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि खबर लिखे जाने तक वीडियो को 6 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। बताते चलें कि कार्तिक आर्यन को करण जौहर की फिल्म 'दोस्ताना 2' से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद ऐसी खबरें भी आईं कि उन्हें शाहरुख खान ने अपनी एक फिल्म से बाहर कर दिया है। फिलहाल, कार्तिक आर्यन फिल्म 'भूल भुलैया 2' और फिल्म 'धमाका' में काम करते दिखाई देंगे।

मर्दों को बचाने के लिए कानून होना चाहिए

श्वेता तिवारी इन दिनों 'खतरों के खिलाड़ी 11' की शूटिंग के लिए केपटाउन में हैं। वहीं, इस बीच एक बार फिर से उनके पति अभिनव कोहली सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने सोशल एकाउंट पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो फादर्स डे पर अपने बेटे से नहीं मिल पाने का दर्द बयां करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो के जरिए मर्दों को बचाने के लिए कानून बनाने की मांग की है। इसके साथ ही इस वीडियो में उन्होंने ये भी बताया है कि वो किस तरह बीते काफी दिनों से बेटे से मिलने की कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन वो हार गए। अभिनव कोहली ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर फादर्स डे के मौके पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि- 'आज फादर्स डे है, आज भी मैं अपने बच्चे को नहीं मिल पाऊंगा। पिछले साल भी नहीं मिल पाया था। बहुत कोशिश की लेकिन मैं हार गया। मैं ये लड़ाई हार गया.कल-परसों श्वेता वापस आ जाएगी। जब मेरे बच्चे की मां उसे छोड़कर चली गई थी और मेरा बच्चा बिना मां-बाप के था, तब डेढ़ महीने तक मैंने बहुत कोशिश की और बहुत हाथ-पैर मारे लेकिन मैं हार गया। मैं उससे नहीं मिल सका।

मेरा हक है कि मैं अपने बच्चे से मिलूं

उन्होंने आगे कहा- मेरे जैसे बहुत सारे आदमी हैं जो कई लड़ाईयां हारे हैं और हार के बैठे हैं लेकिन जंग अभी बाकी है। कई लड़ाईयां हारूंगा मैं लेकिन हर हार से सीखूंगा, शक्ति लूंगा और लड़ता रहूंगा। क्योंकि लड़ना जरूरी है आज मेरे साथ हो रहा है और कल ये मेरे लड़के के साथ होगा। मेरे साथ तो जो होना है वो हो गया लेकिन ऐसा मेरे लड़के के साथ ना हो इसलिए जंग जारी रहेगी। मैं जितनी बार भी हारूंगा उतनी बार ही फिर उठूंगा.क्योंकि ये मेरा हक है कि मैं अपने बच्चे से मिलूं, ये मेरे बच्चे का हक है कि वो अपने बाप से मिले और ये मर्दों का हक है कि उनके खिलाफ कोई गलत कानून ना हो। हमारे इमोशन्स और फीलिंग कुचली ना जाएं और हमारी आजादी छीनी ना जाए'।

मर्दों के लिए कानून

इस वीडियो के साथ अभिनव ने कैप्शन में लिखा- 'बहुत अच्छी बात है कि औरतों की सुरक्षा के लिए स्पेशल कानून हैं लेकिन अब मर्दों के बचाव के लिए कानून चाहिए जो बच्चों को बाप से दूर रखने से और झूठे केस से बचाएं'।

अर्शी की सलमान से अपील : स्वयंबर में ढूंढ़ दें दूल्हा

'बिग बॉस 14' से मशहूर हुईं अभिनेत्री अर्शी खान ने रिएलिटी शो 'स्वयंवर' के साथ टेलीविजन में फिर से अपनी वापसी की हैं। वह चाहती हैं कि बिग बॉस के मेजबान सलमान खान सही जीवनसाथी चुनने में उनकी मदद करें। अर्शी ने बताया, ''मुझे लगता है कि सलमान साहब को शो में दूल्हा ढूंढने में मेरी मदद करनी चाहिए। वह इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने आगे बढ़ने और सफल होने में मेरी मदद की है। उन्होंने मुझे 'बिग बॉस' में जीवन भर का सबक दिया है।'' शो के फॉर्मेट के मुताबिक, इसमें अर्शी खुद यह तय करेंगी कि उनके किसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है यानि कि किसे अपने जीवनसाथी के रूप में चुनना है। 'विष' और 'सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल' जैसे टेलीविजन शोज में नजर आ चुकीं अर्शी का कहना है कि 'स्वयंवर' के बाद उनका प्लान ओटीटी के और अधिक प्रोजेक्ट्स में शामिल होना है।

बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट होंगी जैकलीन फर्नांडिस? 175 करोड़ रुपये का है आलीशान बंगला

बॉलिवुड ऐक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खासा सुर्खियां बटोर रही हैं। ऐक्ट्रेस ने आज तक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कभी भी खुलकर तो बात नहीं की हैं, लेकिन हालिया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जैकलीन जल्द ही जुहू स्थित 175 करोड़ के बंगले में बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रही हैं। ऐक्ट्रेस जिस बिजनेसमैन को डेट कर रही हैं, वह साउथ के रहने वाले हैं। दोनों लिव-इन में रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जैकलीन काफी समय से जुहू और बांद्रा में घर की तलाश कर रही थीं। अब जाकर उन्हें सी- फेसिंग के पास घर मिला है। जिसमें वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहेंगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जैकलीन और उनके बॉयफ्रेंड अपने रिश्ते को लेकर काफी सीरियस हैं। सिर्फ इतना ही नहीं जैकलीन वीडियो कॉल के जरिए लगातार अपने घर को लेकर बॉयफ्रेंड और डिजाइनर से लगातार चर्चा करती रहती हैं। बताते चले कि उन्होंने जो घर फाइनल किया है वह जुहू में प्राइम लोकेशन पर है। जैकलीन के बॉयफ्रेंड जल्द ही अपना काम मुंबई में शिफ्ट करने वाले हैं। हालांकि जैकलीन ने फिलहाल अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। अब वह कब अपने प्यार को जग जाहिर करती हैं यह तो आने वाला वक्त बताएगा।

रकुलप्रीत सिंह करना चाहती हैं कमर्शल फिल्में

बॉलिवुड ऐक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने फिल्म 'यारियां' से साल 2014 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। पहली फिल्म के रिलीज के बाद रकुल ने चार साल का गैप लिया। इस दौरान वह साउथ इंडियन फिल्मों में नजर आईं। रकुल से हाल ही में एक इंटरव्यू में पूछा गया कि साउथ की फिल्मों काम करने के साथ- साथ बॉलिवुड में भी काम करती हैं। तो कभी लैंग्वेज को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई? इस पर रकुल कहती हैं, 'मैं कभी लैंग्वेज को लेकर नहीं सोचती। ऐक्टिंग की कोई सीमा नहीं होती। मुझे अभी कई कमर्शल फिल्में करनी है और बॉलिवुड में अभी मुझे ढंग से नाच-गाना करना बाकी है।' रकुल कहती हैं, 'साउथ हो या बॉलिवुड मुझे दोनों में बैलेंस बनाने आता है, क्योंकि मैं वर्कहॉलिक हूं। यदि आपकी लाइफ पूरी तरह से बैलेंसड हैं तो आप एक दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं जल्दी सोती हूं और जल्दी उठती हूं।' बताते चलें कि रकुल उन चंद ऐक्ट्रेसेस में से हैं, जो साउथ से लेकर बॉलिवुड में अपनी एक खास पहचान बनाई हैं। रकुल आखिरी बार अजय देवगन के साथ फिल्म 'दे दे प्यार दे' में नजर आई थीं। रकुल से जब पूछा गया है कि क्या बॉलिवुड में पैर जमाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा? इस पर ऐक्ट्रेस कहती हैं, 'ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आउटसाइडर से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं कभी भी आउटसाइडर और इंसाइडर जैसी चीजों को नहीं मानती। मेरा बस इतना मानना है कि आपकी प्रतिभा ही आपको आगे तक ले जाती है। अगर आप मेहनती और प्रतिभाशाली हैं तो लोग आपको ऑफर देंगे। कॉनटेक्ट या जान पहचान होने से बस आपको मदद मिल सकती हैं, लेकिन असली खेल पब्लिक के हाथ में है, वही आपको पसंद या ना पसंद करते हैं।' रकुल ने अपनी फिल्मों के लेकर बताया कि उनकी दो फिल्में रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। दो की शूटिंग पूरी हो चुकी है, वहीं दो की शूटिंग शुरू होने वाली है। फिल्म रिलीज को लेकर रकुल कहती हैं, 'महामारी की वजह से जो स्थिती बनी हुई है इसमें यह कहना मुश्किल है कि फिल्म थियेटर में रिलीज होगी। मेरी कुछ फिल्में पिछले साल रिलीज होने वाली थी और कुछ प्रोजेक्ट्स इसी महामारी की वजह से रुकी हुई हैं। सबकुछ ठीक रहता तो शायद शूटिंग पूरी हो जाती।' रकुल आगे कहती हैं, 'मैं इस बात से खुश हूं कि इस महामारी के दौर में भी मेरे पास काफी काम है और मुझे अपनी बुनियादी जरूरतों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैं आभारी हूं।'

WTC Final: नील वैगनर का बैकफुट रिटर्न क्रीज के पार होने के बावजूद जडेजा को दिया आउट, फैन्स भड़के

नई दिल्ली. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल में दो दिनों तक बारिश के कारण खेल रोके जाने के बाद भी न्यूजीलैंड ने रिजर्व डे यानि के छठे दिन भारत को आठ विकेट से हराकर खिताब जीत लिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने 106 रन के अंदर ही भारत के आठ विकेट आउट करके उसे 170 रन पर समे?ट दिया और 139 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। हालांकि भारतीय पारी के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब रवींद्र जडेजा के आउट होने के बाद फैन्स भड़क गए।

लंच के बाद कीवी गेंदबाज नील वैगनर ने जडेजा को काफी छोटी गेंदें डाली और अधिकतर समय तक उन्हें बैकफुट पर धकेले रखा। इसी बीच, वैगनर ने एक ऐसी गेंद डाली जोकि जडेजा के बल्ले का किनारा लेते हुए सीधे विकेटकीपर बीजे वाटलिंग के दस्तानों में कैद हो गई। लेकिन थर्ड अंपायर को देखना पड़ा कि क्या वैगनर का बैकफुट रिटर्न क्रीज को पार तो नहीं कर रहा था क्योंकि विकेटटेकिंग डिलीवरी के समय वह अपनी क्रीज को पार कर गए थे। एक रिप्ले में साफ दिख रहा था कि गेंदबाज का पैर रिर्टन क्रीज को क्रॉस कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद थर्ड अंपायर ने जडेजा को आउट दे दिया।

अंपायर के इस फैसले से फैन्स भड़क गए क्योंकि नियमों के मुताबिक, गेंदबाज के पैर की लैंडिंग पोजीशन रिटर्न क्रीज को नहीं छूनी होनी चाहिए ताकि इसे लीगल डिलीवरी माना जाए। इस नियम के अनुसार, नील वैगनर का बैकफुट रिटर्न क्रीज के पीछे था और हालांकि बाद में पैर आगे निकल गया, लेकिन गेंद के साथ कोई समस्या नहीं थी। इसलिए, जडेजा को आउट दिया गया और थर्ड अंपायर ने इसे नो-बॉल देना उचित नहीं समझा।

टीम इंडिया ने गंवाया WTC खिताब, सचिन तेंदुलकर ने बताया कहां हुई चूक

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम ने 2013 के बाद से कोई आईसीसी (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) ट्रॉफी नहीं जीती है। पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया ने आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट या फाइनल तक जगह बनाई है, लेकिन खिताब पर कब्जा नहीं जमा पाई है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। एक समय लग रहा था कि विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया आईसीसी ट्रॉफी का आठ साल का सूखा खत्म करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड ने आठ विकेट से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम कर लिया। मास्टर ब्लास्टर

सचिन तेंदुलकर ने बताया है कि टीम इंडिया से कहां चूक हुई।

मैच के बाद सचिन ने ट्विटर पर लिखा, 'वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 जीतने के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बधाई। आप बेहतर टीम निकली, टीम इंडिया अपने प्रदर्शन से निराश होगी। मैंने जैसा कि कहा था कि पहले 10 ओवर बहुत अहम होंगे और भारत ने विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा दोनों का विकेट 10 गेंद के अंदर गंवा दिया, जिससे टीम पर काफी ज्यादा दबाव आ गया।'

साउथम्प्टन में खेले गए इस ऐतिहासिक मैच पर मौसम की काफी मार पड़ी। पहले और चौथे दिन का खेल तो पूरी तरह से बारिश में धुल गया, जिसके चलते मैच के रिजल्ट के लिए रिजर्व डे का इस्तेमाल करना पड़ा। इस मैच के लिए आईसीसी ने 23 जून को रिजर्व डे के तौर पर रखा था। टीम इंडिया ने 64 रन पर दो विकेट से आगे खेलना शुरू किया और 170 रनों तक ऑलआउट हो गई। न्यूजीलैंड ने 139 रनों का टारगेट दो विकेट गंवाकर हासिल कर लिया।

WTC FINAL : खिताब हारकर भी करोड़पति बनी टीम इंडिया, मिले इतने करोड़ रुपये

नई दिल्ली. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल में न्यूजीलैंड हाथों खिताब हारने के बाद टीम इंडिया और फैंस के अंदर निराशा छाई हुई है। विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम एक बार फिर से कोई आईसीसी खिताब जीतने में असफल रही। मैच का फैसला रिजर्व डे को यानी के छठे दिन जाकर हुआ। न्यूजीलैंड की टीम ने केन विलियमसन की कप्तानी में साउथम्पटन के द एजिस बाउल मैदान पर खेले गए डब्ल्यूटीसी के फाइनल में भारत को आठ विकेट से हराकर पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया।

हालांकि खिताब हारने के बाद भी टीम इंडिया मालमाल हो गई है। आईसीसी ने फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही पुरस्कार राशि की घोषणा कर दी थी। इसके मुताबिक, विजेता न्यूजीलैंड को 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि के करीब 12 करोड़ रुपये मिले। इस प्राइज मनी के अलावा कीवी टीम ने शानदार टेस्ट गदा भी अपने नाम कर लिया। उपविजेता भारत को 800,000 अमेरिकी डॉलर यानि के करीब 5.94 करोड़ रुपये मिले। न्यूजीलैंड ने प्वाइंटस टेबल में टॉप पर रहते हुए जबकि भारत ने दूसरे स्थान पर रहते हुए डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था।

आईसीसी के मुताबिक, नौ टीमों के इस टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 4.5 लाख डॉलर (लगभग 3.3 करोड़ रुपये) और चौथे स्थान पर रहने वाली टीम को 3.5 लाख डॉलर (लगभग 2.5 करोड़ रुपये) की प्राइज मनी मिलेगी। वहीं, पांचवें स्थान पर रहने वाली टीम को दो लाख डॉलर (लगभग 1.46 करोड़ रुपये) जबकि बाकी के चार टीमों को एक-एक लाख डॉलर (लगभग 73 लाख रुपये) की पुरस्कार राशि दी जाएगी।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के विजेता को तय करने के लिए विराट कोहली ने सुझाया 'बेस्ट ऑफ थ्री' का फॉर्मूला, माइकल वॉन ने उठाए सवाल

नई दिल्ली. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खिताब को अपने नाम करने का भारतीय टीम का सपना साकार नहीं हो सका। केन विलियमयन की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने बारिश से ्रभावित डब्ल्यूटीसी के फाइनल में भारत को 8 विकेट से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन कहलाने का गौरव हासिल किया। टीम इंडिया की इस हार से भारतीय फैन्स का दिल टूट गया है। हार के बाद भारतीय कप्तान ने डब्ल्यूटीसी फाइनल के फॉर्मेट को लेकर सवाल उठाए और कहा कि विजेता का फैसला ब्रेस्ट ऑफ थ्री से यानी तीन मैचों की सीरीज से तय होना चाहिए। इसी बीच, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन को विराट का यह सुझाव बिलकुल पसंद नहीं आया है और उन्होंने आईसीसी के मौजूदा फॉर्मेट को एकदम सही करार दिया है।

विराट कोहली ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैं इसका पक्ष में नहीं हूं कि दुनिया की बेस्ट टेस्ट टीम का निर्धारण एक फाइनल मैच से हो। अगर टेस्ट सीरीज है तो तीन टेस्ट से ही पता चलता है कि किस टीम में वापसी की क्षमता है। ऐसा नहीं होता कि दो दिन अच्छा खेले और फिर आप अचानक अच्छी टेस्ट टीम नहीं हैं। मैं यह नहीं मानता। भविष्य में इस पर विचार किया जाना चाहिए। तीन मैचों में प्रयास होते हैं, उतार चढाव होते हैं, हालात बदलते हैं। गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। इसके बाद पता चलता है कि बेस्ट टीम कौन सी है।'

कोहली के सुझाव पर माइकल वॉन ने ट्वीट करते हुए लिखा, %यह किस शेड्यूल में फिट होगा? क्या आईपीएल फाइनल वाले साल में अपने दो हफ्तों का कम करेगा ताकि फाइनल का शेड्यूल फिट हो सके? मुझे इस पर संदेह है। फाइनल मैच एक ही होता है.

चहल ने सोशल मीडिया पर डाला वर्कआउट का वीडियो, फैंस के साथ साथ पूर्व क्रिकेटर ने भी लिए मजे

अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को भारतीय क्रिकेट टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर जाना हैं। इस दौरे के लिए व?ह अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रे हैं और खुद को फिट रखने के लिए जमकर जिम में वर्कआउट कर रहे हैं। मजाकिया अंदाज को लेकर चहल अक्सर सोशल मीडिया पर फैंस के बीच चर्चा में बने रहते हैं।

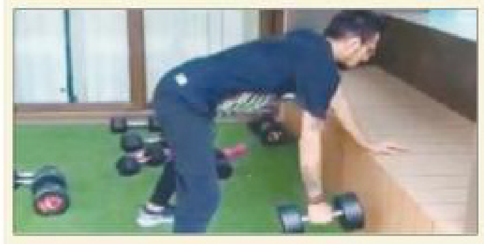

युजी ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट? किया है, जिसमें वह वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

चहल के इस नए वीडियो पर फैंस के साथ साथ पूर्व क्रिकेटर भी उनसे मजे ले रहे हैं। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर साजिद महमूद ने कमेंट करते हुए उन्हें सलमान खान बने जाने की बात कही है। हालांकि चहल ने भी इन कमेंटों पर मजेदार जवाब दिए हैं। चहल ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, यह सब ताकत के बारे में है...शारीरिक और मानसिक रूप से भी। इस पर महमूद ने कमेंट करते हुए लिखा, %बहुत जल्द सलमान खान बन जाओगे।' भारतीय स्पिनर ने पूर्व क्रिकेटर के कमेंट पर जवाब देते हुए दुनिया के महान बॉडी बिल्डरों में से एक आर्नोल्ड श्वार्जनेगर तक का जिक्र कर डाला। चहल ने जवाब देते हुए लिखा, %आर्नोल्ड श्वार्जनेगर के बारे में क्या ख्याल है।% वहीं, एक यूजर ने लिखा, 'ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी।' वीडियो को अब तक करीब 23000 लाइक मिल चुके हैं। चहल इस समय मुंबई में श्रीलंका दौरे पर जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के साथ क्वारंटीन में हैं। इस दौरे के लिए सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को कप्तान जबकि तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को उपकप्तान बनाया गया है।

WTC Final 2021: कप्तान विराट के बयान के बाद इन 4 खिलाड़ियों पर मंडरा रहा सबसे ज्यादा खतरा

नई दिल्ली. बुधवार को WTC Final 2021 में न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार के बाद न केवल करोड़ों भारतीय प्रशंसकों और पूर्व क्रिकेटरों में खासा रोष है, बल्कि कप्तान विराट कोहली ने मैच के बाद वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया है कि टेस्ट टीम में बदलाव किए जाएंगे और जीत के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों को टीम में लाया जाएगा. निश्चित ही, कोहली के इस बयान के बाद कुछ खिलाड़ियों पर अब तलवार लटक गयी है. समझा जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज इनके लिए आखिरी मौका हो सकती है. या बीच में ही इलेवन से दूर किया जा सकता है. बहरहाल हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं, जिनके लिए इस समय सबसे ज्यादा खतरा पैदा हो गया है और क्यों हो गया है.

1. चेतेश्वर पुजारा

विराट के बयान के बाद सबसे ज्यादा खतरा टीम इंडिया की दूसरी वॉल कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा पर मंडरा रहा है. जिस तरह की क्रिकेट विराट खेलना चाहते हैं, अब पुजारा के लिए यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि यही 'उनका खेलने का तरीका है'.पुजारा ने फाइनल में पहली पारी में 54 गेंदों पर 8 रन बनाए, तो दूसरी पारी में जब हालात के लिहाज से तेज रन बनाने की दरकार थी, तो पुजारा ने 80 गेंदों पर 15 रन बनाए. जाहिर है विराट ब्रांड क्रिकेट में अब पुजारा अनफिट हो चुके हैं.

2. जसप्रीत बुमराह

भारतीय गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा निराश किया और अब उन पर खतरा मंडरा गया है. पिछले काफी लंबे समय से बुमराह उम्मीदों से बहुत पीछे रह जा रहे हैं. फाइनल में पहली पारी में सिर्फ वही थे, जिन्हें 26 ओवर डालने के बावजूद कोई विकेट नहीं मिला, तो दूसरी पारी में उनकी झोली खाली रही. इंग्लैंड दौरे में भारत कई युवा पेसरों को साथ लेकर गया है. कौन जानता है कि कब बुमराह इलेवन से

बाहर हो जाएं और कोई युवा जगह बना ले.

3. अजिंक्य रहाणे

यह सही है कि रहाणे ड्ढ्ढञ्ज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में अव्वल भारतीय रहे. रहाणे ने 18 टेस्ट में 3 शतक और 6 अर्द्धशतकों से 42.92 के औसत से 1159 रन बनाए हैं, लेकिन उनका 46.84 का स्ट्राइक-रेट ब्रांड विराट क्रिकेट में फिट नहीं बैठ रहा. हालांकि, वह टीम के उप-कप्तान हैं, लेकिन अब रहाणे को रन बनाने की गति के साथ ही स्थायित्वता पर ध्यान देना होगा. हालांकि, बाकी खिलाड़ियों की तुलना में रहाणे र खतरा बहुत कम है. लेकिन उन्हें ब्रांड विराट क्रिकेट में फिट होने पर काम करना ही होगा. यह न भूलें कि केएल राहुल जैसा बल्लेबाज बाहर बैठा हुआ है.

4. शुबमन गिल

यह सही है कि शुबमन गिल भारत का भविष्य हैं, लेकिन वह टीम की जरूरतों को पूरा नहीं कर स्के. वहीं, एक धड़े ने यह सवाल उठाया कि आखिर बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले मयंक अग्रवाल की जगह गिल को क्यों खिलाया गया. वर्ल्ड चैंपियनशिफ में गिल ने 8 टेस्ट मे 31.84 के औत से 4414 रन बनाए. न तो औसत के पैमाने पर भी गिल खरे उतरे और न ही टीम को स्थायित्व साझेदारी देने के लिहाज से. अगर इंग्लैंड सीरीज में बतौर ओपनर मयंक की इंट्री हो जाती है, तो आप चौंकिएगा बिल्कुल मत.

भारत-न्यूजीलैंड के नहीं ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन ने बनाए हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन

नई दिल्ली. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथम्पटन के एजिस बाउल मैदान पर खेला गया। न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। न्यूजीलैंड के सामने टीम इंडिया ने जीत के लिए 139 रनों का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को कीवी टीम ने अपनी दूसरी पारी में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन 52 और रॉस टेलर 47 रन बनाकर नॉटआउट रहे। भारत दूसरी पारी में महज 170 रनों पर ऑलआउट हो गई।

साल 2019 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। भारत को हराकर कीवी टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी कीवी टीम टॉप पर है। दो साल पहले शुरू हुई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो मार्नस लाबुशेन इस चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होने इस चैंपियनशिप में 1675 रन बनाए। लाबुशेन ने 23 पारियों में 72.82 की औसत से ये रन बनाए। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट हैं। उन्होंने 37 पारियों में 47.42 की औसत से 1660 रन बनाए।ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 22 पारियों में 63.85 की औसत से 1341 रन बनाए। एशेज 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ स्मिथ ने एक साल के प्रतिबंध के बाद वापसी की थी, जो डब्ल्यूटीसी का भी पहला मैच था। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने डब्ल्यूटीसी में 1334 रन बनाए। इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर भारत के अजिंक्य रहाणे हैं। उन्होंने 1159 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ डब्ल्यूटीसी के फाइनल मुकाबले में उन्होंने पहली पारी में 49 और दूसरी पारी में 15 रन बनाए। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 के आखिरी तीन मैचों में भारतीय टीम के कप्तान थे। भारत नेये सीरीज 2-1 से जीती थी।

WTC Final: रिजर्व डे के आखिरी सेशन में पंत की जगह साहा ने की विकेटकीपिंग, दिल्ली कैपिटल्स ने बताई ये वजह

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों आठ विकेट से हारकर एक बार फिर से आईसीसी ट्रॉफी जीतने से चूक गई। 2013 के बाद से विराट कोहली के कप्तान रहते हुए टीम इंडिया ने अब तक एक बार भी आईसीसी टूर्नामेंट खिताब नहीं जीता है। डब्ल्यूटीसी फाइनल में भारतीय टीम ने रिजर्व डे की शुरुआत दो विकेट पर 64 रन से आगे खेलते हुए की और उसके पास 32 रनों की बढ़त थी। ऐसे में मैच का परिणाम किसी भी ओर जा सकता था। हालांकि मैच में एक बार फिर से सबकी निगाहें विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पर लगी थी। लेकिन पंत भी कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए और 88 गेंदों पर 41 रन ही बना पाए।

बल्लेबाजी के बाद पंत के पास विकेट के पीछे भारतीय गेंदबाजों को विकेट दिलाने में मदद करने की जिम्मेदारी थी। लेकिन पंत इसमें भी असफल रहे क्योंकि रिजर्व डे के आखिरी सेशन में वह मैदान से बाहर चले गए और उनकी जगह रिद्धिमान साहा ने विकेट के पीछे की जिम्मेदारी संभाली। पंत के मैदान से बाहर जाने के बाद कमेंटेटर इयान बिशन ने कहा कि पंत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए बाहर गए हैं।

युवा बल्लेबाज पंत आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं। पंत के मैदान से बाहर जाने पर अब दिल्ली कैपिटल्स की ओर से भी बयान आ गया है। दिल्ली कैटिपल्स ने टिवटर पर लिखा, %ऋषभ पंत अस्वस्थ हैं और उनकी जगह रिद्धिमान

साहा विकेटकीपिंग कर रहे हैं।'

पंत के अस्वस्थ होने से फैन्स चिंतित हो गए हैं क्योंकि टीम इंडिया को चार अगस्त से इंग्लैंड के साथ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। पंत हाल के समय में नियमित रूप से भारतीय टीम का हिस्सा हैं और ऐसे में उनका अस्वस्थ होना टीम इंडिया के खतरे की घंटी हो सकती है। मौजूदा समय पंत और साहा ही विकेटकीपर के रूप में टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के साथ नियमित रूप से बने हुए है। इनमें पंत ने साहा के मुकाबले ज्यादा मैच खेले हैं।